• वर्ष–5
• अंक–270
रायपुर, रविवार
28 जून 2026
• पृष्ठ–8
• मूल्य–3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज–8>> नक्सल मुक्त बस्तर के नव निर्माण...

भारत और सेशेल्स के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे

सेशेल्स पहुंचे मोदी, राष्ट्रपति हर्मिनी ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन दिन की यात्रा पर शनिवार को सेशेल्स पहुंच गये जहां राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने खुद हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।बाद में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी श्री मोदी का हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने सेशेल्स दौरे पर कहा– सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर का प्रमुख साझेदार है। इस साल भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के संबंध आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और लोगों के गहरे जुड़ाव पर आधारित हैं।

श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी।प्रधानमंत्री ने लिखा, सेशेल्स पहुँचा। हवाई अड्डे पर डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत के लिए हार्दिक आभार। सेशेल्स को हिन्द महासागर में बहुमूल्य समुद्री साझेदार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सेशेल्स हिन्द महासागर में एक मूल्यवान समुद्री साझेदार और घनिष्ठ मित्र है। इस यात्रा के दौरान हमारे लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने तथा हमारे देशों के लोगों के हित में सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक चर्चा की अपेक्षा है।

अल्डाब्रा जायंट टॉर्टोइज से जुड़ा भारत का खास रिश्ता

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अल्डाब्रा जायंट टॉर्टोइज सेशेल्स की पहचान हैं और दुनिया की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली कछुआ प्रजातियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनका भारत और सेशेल्स की मित्रता से भी विशेष संबंध है। वर्ष 2014 में सेशेल्स ने दो विशाल कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार स्वरूप दिए थे। इसके बाद हैदराबाद चिड़ियाघर को भी ऐसे कछुए भेंट किए गए। इतिहास

'कोको डी मेर' का पौधा लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने संयुक्त रूप से 'कोको डी मेर' का पौधा भी लगाया। यह दुर्लभ वृक्ष सेशेल्स का राष्ट्रीय गौरव माना जाता है और देश के कोट ऑफ आर्म्स पर भी अंकित है। इसके बीज दुनिया के सबसे बड़े और फल सबसे भारी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सेशेल्स जैव विविधता संरक्षण तथा पर्यावरण सुरक्षा के साझा संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

भारतीय मूल के लोगों से जुड़े हैं ऐतिहासिक रिश्ते

करीब 1.20 लाख की आबादी वाले सेशेल्स में लगभग हर आठवां नागरिक भारतीय मूल का है। देश के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन के पूर्वज भी बिहार के गोपालगंज से थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बंगाल में लागू होगा यूसीसी और धर्मांतरण विरोधी कानून

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार जल्द ही समान नागरिक संहितालागू करने जा रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून भी लागू किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा– हमें कुछ समय दें। पश्चिम बंगाल में धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून लागू किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा– हमें कुछ समय दें। पश्चिम बंगाल में धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून बनाएगी और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के उपायों के तहत राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी।

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर रवींद्र सदन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा के माध्यम से घुसपैठ ने धर्मांतरण, लव जिहाद और डेमोग्राफिक बदलावों में योगदान दिया है।

उन्होंने कहा, हमें कुछ समय दें। पश्चिम बंगाल में धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून और समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

यह दावा करते हुए कि उनकी सरकार ने सीमा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराकर सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में घुसपैठियो की पहचान करने और उन्हें उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जो लोग अवैध रूप से प्रवेश करते हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।

अवैध प्रवासियों और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत आने वाले शरणार्थियों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हिंदू घुसपैठिए नहीं हैं और उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी।उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार किसी भी ताकत को पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान या राष्ट्र को कमजोर नहीं करने देगी।वंदे मातरम को देश के लिए संजीवनी मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि यह गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

रायपुर. कभी नक्सल संगठन का मजबूत गढ़ और बस्तर में नक्सलियों की मांद कहे जाने वाले उत्तर बस्तर कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम किसकोड़ो में ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। जिस स्थान पर कभी नक्सलियों की चौपाल लगती थी, वहीं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने देर शाम को ग्रामीणों के बीच जनचौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनीं। (**विस्तृत समाचार पेज–8 पर**)

अगली पीढ़ी के रॉकेट इंजन का किया सफल परीक्षण

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनने बताया कि उसने अपने सेमी–क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड का 'हॉट टेस्ट' सफलतापूर्वक किया। यह परीक्षण इंजन की लक्षित क्षमता (थ्रस्ट) के 88% स्तर पर किया गया, जो एक नए प्रोपल्शन सिस्टम (प्रणोदन प्रणाली) के विकास में एक अहम उपलब्धि है।

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 24 जून को तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किए गए इस परीक्षण में इंजन के पावर हेड का 175 टन के थ्रस्ट लेवल पर स्थिर संचालन देखा गया।

इसरो ने बताया कि यह सफल परीक्षण, पहले किए गए 47% और 60% थ्रस्ट वाले परीक्षणों के बाद हुआ है। एजेंसी ने कहा कि इस नई उपलब्धि से 200 टन के फुल–थ्रस्ट प्रदर्शन (पूरे थ्रस्ट के साथ परीक्षण) की दिशा में आगे बढ़ने के लिए काफी भरोसा मिलेगा।सेमी–क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज को भारत के एलवीएम 3 लॉन्च व्हीकल पर मौजूद रु10 कोर स्टेज की जगह लेने के लिए विकसित किया जा रहा है। 2,000–किलोन्यूटन वाले एसई 2000 इंजन से चलने वाले इस अपग्रेड से पेलोड क्षमता और ऑपरेशनल दक्षता (काम करने की क्षमता) में सुधार होने की उम्मीद है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन–आधारित ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा।

प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिन की यात्रा पर सेशेल्स रवाना

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तीन दिन की यात्रा पर सेशेल्स के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान वे उस देश के नेशनल डे के गोल्डन जुबली समारोह में शामिल होंगे और दोस्ती को और मज़बूत करने के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। अपनी

रवानगी के समय दिए बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स एक अहम समुद्री पड़ोसी है और विज़न महासागर तथा ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता में एक मुख्य साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मज़बूत करने के मकसद से होने वाली बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि हम मिलकर अपने लोगों की तरक्की के लिए काम करेंगे और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह सेशेल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी के निमंत्रण पर 27 से 29 जून तक सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं।

राम मंदिर चंदा चोरी में लीपापोती नहीं, पूरी जांच चाहिए : प्रियंका

नईदिल्ली। कांग्रेस महासचिव और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी

गड़बड़ियाँ सिर्फ़ निचले स्तर के कर्मचारी ही कर सकते हैं और ऊँचे स्तर के लोगों की मिलीभगत की ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा कि यह सवाल भी अहम है: क्या सिर्फ़ निचले स्तर के कर्मचारी अपने दम पर सीसीटीवी कैमरे बंद कर सकते हैं और हज़ारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है? उन्होंने मामले को दबाने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी देते हुए निष्पक्ष जांच और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच के नाम पर लीपा–पोती करने के बजाय पारदर्शी जांच होनी चाहिए। और चोरी की इस घटना में जो भी शामिल है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी नियुक्त किया

नईदिल्ली। बसपा प्रमुख मायावती से मिलने की नाकाम कोशिश के कुछ हफ़्ते बाद, कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम को यूपी के लिए ऑल–इंडिया कांग्रेस कमेटी का इंचार्ज नियुक्त किया गया। यह आदेश पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी

किया। गौतम ने अविनाश पांडे की जगह ली है, जिन्होंने दिसंबर 2023 में यह ज़िम्मेदारी संभाली थी। इस नियुक्ति को दलितों और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के बीच अपनी पैठ मज़बूत करने की पार्टी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पेशे से वकील गौतम, 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले एक अंबेडकरवादी एक्टिविस्ट के तौर पर चर्चा में आए थे। वे अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2022 में, बौद्ध धर्म अपनाने के एक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद गौतम कांग्रेस में शामिल हो गए और 2025 में एआईसीसी के अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन बनाए गए।

राजनाथ ऑपरेशन सिंदूर पर गुमराह किया या अनजान थे?

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आलोचना की। यह आलोचना नेशनल वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए छह सुरक्षाकर्मियों के नाम उकेरे जाने के बाद की गई। एक्स पर एक पोस्ट में, खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राजनाथ सिंह के

संसदीय भाषण का एक क्लिप शेयर किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ़ भारत की जवाबी कार्रवाई से जुड़ी हालिया घटनाओं को लेकर केवल दो ही स्थितियां संभव हैं। खेड़ा ने कहा कि या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद में बोलते समय यह पता नहीं था कि छह सैनिक पहले ही शहीद हो चुके हैं। अगर ऐसा है, तो मंत्री पर गंभीर सवाल उठता है कि उन्हें उसी मंत्रालय के बारे में जानकारी नहीं है जिसके वे प्रमुख हैं। या फिर, उन्हें सच पता था और फिर भी उन्होंने संसद को गुमराह किया। यह बात और भी गंभीर है, क्योंकि इससे साबित होता है कि यह सरकार लोकतंत्र के मंदिर में देश से झूठ बोलती है।

पाला बदलने वाले सांसदों पर भड़के उद्धव ठाकरे

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) में चल रही राजनीतिक उथल–पुथल के बीच, पार्टी नेता उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि असली शिवसैनिक अभी भी उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने उन बागी सांसदों की आलोचना की जो हाल ही में शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। यवतमाल के दौरे पर

पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ठाकरे ने बगावत पर शर्मिंदगी ज़ाहिर की और कहा कि असली शिवसैनिक मेरे साथ हैं। जहाँ तक बाकियों की बात है, आप सभी उनका बर्ताव देख ही रहे हैं। मुझे सच में शर्म आती है कि वे इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे। यह दौरा यवतमाल–वाशिम के सांसद संजय देशमुख के पाला बदलने के बाद हुआ; वे उन छह शिवसेना (यूबीटी) सांसदों में से एक थे जो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे। ठाकरे ने पाला बदलने वाले सांसदों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी सीटें सिर्फ़ उनके प्रचार और जनता के समर्थन की वजह से जीती थीं। उन्होंने कहा कि ये सांसद सिर्फ़ मेरे कहने पर चुने गए थे। अब उनमें यह कहने की हिम्मत है कि अपने चुनाव क्षेत्रों का दौरा करना बेकार है।

नई भाजपा के रोल मॉडल हैं योगी, हेमंत और शुभेंदु!

प्रो. संजय द्विवेदी

उत्तर प्रदेश एक ऐसे मुख्यमंत्री से रूबरू है, जिसे राजनीति के मैदान में बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। उनके बारे में यह ख्यात था कि वे एक खास वर्ग की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनकी राजनीतिक शैली से पूरी तरह सहमत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह अपनी पकड़ बनाई है और देश में एक अलग माडल खड़ा दिया है, वह सर्वत्र चर्चा का विषय है। इससे यह भी साबित हो रहा है कि 'अपनी राजनीति' के प्रति भाजपा का आत्मदैन्य कम हो रहा है। वहीं असम में हेमंत विश्वशर्मा उम्मीदों का चेहरा बनकर उभरे हैं, असम में तीसरी बार सरकार बनाकर भाजपा ने पूर्वोत्तर में इतिहास रच दिया है। इसी तरह गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति से पश्चिम बंगाल की विजय ऐतिहासिक कही जा रही है और वहां बने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ फैसलों ने जनविश्वास की हिलोरें पैदा की हैं। जड़ता को तोड़कर एक नई उम्मीद बनी है। केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगमन ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदलकर रख दिया है।

भाजपा का आज तक का ट्रैक हिंदुत्व का वैचारिक और राजनीतिक इस्तेमाल कर सत्ता में आने का रहा है। देश की राजनीति में चल रहे विमर्श में भाजपा बड़ी चतुराई से इस कार्ड का इस्तेमाल तो करती थी, किंतु उसके नेतृत्व में इसे लेकर एक हिचक बनी रहती थी। वो हिचक अटल जी से लेकर आडवानी तक हर दौर में दिखी है। भाजपा का हर नेता सत्ता पाने के बाद यह साबित करने में लगा रहता है वह अन्य दलों के नेताओं के कम 'सेकुलर' नहीं है। उत्तर प्रदेश की 'आदित्यनाथ परिघटना' दरअसल भाजपा की वैचारिक हीनग्रंथि से मुक्ति को स्थापित करती नजर आती है। नरेंद्र मोदी के राज्यारोहण के बाद योगी आदित्यनाथ का उदय भारतीय राजनीति में एक अलग किस्म की राजनीति की स्वीकृति का प्रतीक है। एक धर्मप्राण देश में धार्मिक प्रतीकों, भगवा रंग, सन्यासियों के प्रति जैसी विरक्ति मुख्यधारा की राजनीति में दिखती थी, वह अन्यत्र दुर्लभ है। भाजपा जैसे दल भी इस सेकुलर विकार से कम ग्रस्त न थे। धर्म और धर्माचार्यों का इस्तेमाल, धार्मिक आस्था का दोहन

और सत्ता पाते ही सभी धार्मिक प्रतीकों से मुक्ति लेकर सारी राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण में लग जाती थी। प्रधानमंत्रियों समेत जाने कितने सत्ताधीशों के ताज जामा मस्जिद में झुके होगें, लेकिन हिंदुत्व के प्रति उनकी हिचक निरंतर थी।

यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं की एक समय में दीनदयाल जी उदार थे, तो अटलजी और बलराज मधोक अपनी वक्रता के चलते उग्र नेता माने जाते थे। अटलजी का दौर आया तो लालकृष्ण आडवाणी उग्र कहे जाने लगे, फिर एक समय ऐसा भी आया जब आडवानी उदार हो गए और नरेंद्र मोदी उग्र मान जाने लगे। आज की व्याख्याएं सुनें– नरेंद्र मोदी उदार हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह उग्र माने जाने लगे हैं। अब तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी आदित्यनाथ की परंपरा के मुख्यमंत्री कहे जाने लगे हैं।

यह मीडिया, बौद्धिकों की अपनी रोज बनाई जाती व्याख्याएं हैं। लेकिन सच यह है कि अटल, मधोक, आडवानी, मोदी, अमित शाह या आदित्यनाथ, हेमंत विश्वशर्मा और शुभेंदु अधिकारी कोई अलग–अलग लोग नहीं है। एक विचार के प्रति समर्पित राष्ट्रनायकों की सूची है यह। इसमें कोई कम जा ज्यादा उदार या कठोर नहीं है। किंतु भारतीय राजनीति का विमर्श ऐसा है जिसमें वास्तविकता से अधिक ड्रामे पर भरोसा है। भारतीय राजनेता की मजबूरी है कि वह टोपी पहने, रोजा भले न रखे किंतु इफ्तार की दावतें दे। आप ध्यान दें सरकारी स्तर पर यह प्रहसन लंबे समय से जारी रहा है। भाजपा भी इसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। उसमें भी इस तरह के रोग हैं। वह भी राष्ट्रनीति के साथ थोड़े तुष्टिकरण को गलत नहीं मानती। जबकि उसका अपना नारा रहा है सबको न्याय, तुष्टिकरण किसी का नहीं। उसका एक नारा यह भी रहा है–राम, रोटी और इंसाफ। लंबे समय के बाद भाजपा में अपनी वैचारिक लाइन को लेकर गर्व का बोध दिख रहा है। असरे बाद वे भारतीय राजनीति के सेकुलर संक्रमण से मुक्त होकर अपनी वैचारिक भूमि पर गरिमा के साथ खड़े दिख रहे हैं। समझौतों और आत्मसमर्पण की मुद्राओं के बजाए उनमें अपनी वैचारिक भूमि के प्रति हीनताग्रंथि के भाव कम हुए हैं। अब वे अन्य दलों की नकल के बजाए एक वैचारिक लाइन लेते हुए दिख रहे हैं। दिखावटी सेकुलरिज्म के बजाए वास्तविक राष्ट्रीयता के उनमें दर्शन हो रहे हैं। मोदी जब एक सौ चालीस करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं तो बात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से ऊपर चली जाती है। यहां देश सम्मानित होता है, एक नई राजनीति का प्रारंभ दिखता है। एक भगवाधारी संन्यासी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है।

गरी में हल्दी की वैज्ञानिक खेती को मिलेगा नया आयाम

250 किसानों ने खरीदे 10 टन गुणवत्तायुक्त बीज, 250 टन उत्पादन का लक्ष्य

धमतरी। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में हल्दी की वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत झुझरकस्सा के आश्रित ग्राम कोर्रेमुडा में जिला पंचायत धमतरी, जनपद पंचायत नगरी एवं प्रदान संस्था के संयुक्त सहयोग से हल्दी की वैज्ञानिक खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण में नगरी एवं मगरलोड विकासखंड के कृषि मित्रों और पीआरपी ने सहभागिता करते हुए हल्दी उत्पादन की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम का उद्देश्य खेती की वैज्ञानिक पद्धतियों को गांव-गांव तक पहुंचाकर किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं अधिक उत्पादन के लिए तैयार करना है।

प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने भूमि की तैयारी, उन्नत एवं रोगमुक्त बीज (राइजोम) का चयन, बीज उपचार, संतुलित पोषण प्रबंधन, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, फसल संरक्षण, वैज्ञानिक कटाई तथा कटाई उपरांत प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।

साथ ही किसानों को यह भी बताया गया कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ उचित प्रसंस्करण एवं विपणन से हल्दी की खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।

इस पहल के अंतर्गत अब तक 250 किसानों ने गट्टासिल्ली किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) के माध्यम से लगभग 10 टन हल्दी बीज (राइजोम) का क्रय किया है। इन बीजों से लगभग 270 दिनों में 250 टन हल्दी उत्पादन होने का अनुमान है। खेती के प्रत्येक चरण में कृषि मित्रों एवं एफपीओ द्वारा किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं नियमित फील्ड सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

उत्पादित हल्दी का प्रसंस्करण हरिभूमि किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत धमतरी द्वारा कोर्रेमुडा में हल्दी प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर किसानों को मूल्य संवर्धन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रसंस्करण के बाद तैयार हल्दी पाउडर का विपणन गट्टासिल्ली किसान उत्पादक कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर बाजार एवं उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

यह पहल किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर 'उत्पादन-प्रसंस्करण-ब्रांडिंग-विपणन' की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में कृषि आधारित उद्यमिता, किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने तथा मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

हल्दी उत्पादन की यह पहल नगरी क्षेत्र की ऊपरी भूमि के बेहतर उपयोग के साथ किसानों के लिए अतिरिक्त एवं टिकाऊ आय का माध्यम बनेगी। आगामी वर्षों में हल्दी उत्पादन के क्षेत्रफल में विस्तार, वैज्ञानिक खेती, प्रसंस्करण एवं संगठित विपणन की इस समन्वित व्यवस्था से नगरी क्षेत्र को हल्दी उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन के एक उभरते कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में यह पहल मील का पत्थर साबित होगी।

धमतरी में मनाया छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस

शिवाजी महाराज के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया

धमतरी। शहर में शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मराठा समाज की ओर से रत्नाबांधा रोड स्थित छत्रपति शिवाजी चौक में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का विधि-विधान से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा भी शामिल हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के साथ हुई। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का सात पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया। समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित कर शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को याद किया। इस दौरान जय भवानी, जय शिवाजी के जयघोष गूंजते रहे।

मराठा समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यह आयोजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। मराठा समाज के विश्वजीत कृदत्त ने बताया कि ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। करीब साढ़े 350 वर्ष पहले भारत में एक हिंदू सम्राट के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ, जिसकी गौरवगाथा आज भी पूरे समाज द्वारा उत्सव के रूप में मनाई जाती है।

कार्यक्रम में पहुंचे धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिन्होंने साहस, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और सुशासन का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है।

महापौर ने मराठा समाज को राज्याभिषेक उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक गौरव को जीवंत बनाए रखते हैं।

मनेन्द्रगढ़ नर्सिंग कॉलेज भवन निर्माण के लिए 8.68 करोड़ की स्वीकृति

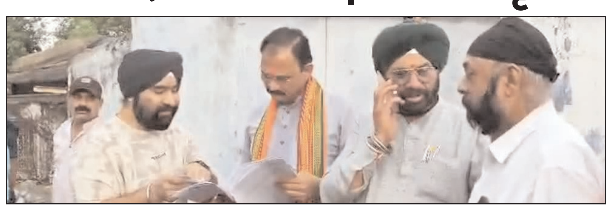

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जिले में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ के भवन निर्माण के लिए करीब 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस स्वीकृति के बाद जिले में नर्सिंग शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास का रास्ता साफ हो गया है।

स्वीकृत राशि के तहत मनेन्द्रगढ़ स्थित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में बुनियादी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ लोक स्वास्थ्य एकीकरण से जुड़े भवन निर्माण कार्य भी शामिल किए गए हैं। नए भवन के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होती है। नर्सिंग महाविद्यालय का मजबूत अधोसंरचना विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को और सशक्त करेगा। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। मनेन्द्रगढ़ नर्सिंग महाविद्यालय भवन की स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मट्टी मरका में कलेक्टर की रात्रिकालीन चौपाल

ग्रामीणों से पर्यटन आजीविका और विकास पर सीधा संवाद

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मट्टी मरका गांव में रात्रिकालीन चौपाल लगी। इस चौपाल में कलेक्टर विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक डॉ। जितेंद्र यादव, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मीणा शामिल हुए। अधिकारियों ने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनीं। विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर विश्वदीप ने ग्रामीणों की जीवनशैली, आजीविका के प्रमुख साधनों और दैनिक आवश्यकताओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि शासन का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन करना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार लाना भी है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझ रहा है और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि ग्राम मट्टी मरका प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। यदि इस क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो यह पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। उन्होंने ग्रामीणों को होम स्टे, इको स्टे और इको टूरिज्म जैसी गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

कलेक्टर ने बताया कि पर्यटन के विकास से स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। गांव आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। ग्रामीणों ने प्रशासन की पहल का स्वागत किया और हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

ग्रामीणों ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, नए चेकडैम निर्माण, हैंडपंप स्थापना, तालाबों के गहरीकरण, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास की मांग रखी। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर विश्वदीप ने गांव के कई घरों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर उन्हें समय-सीमा के भीतर आवास निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया।

राजनांदगांव में हिट एंड रन केस

बच्ची को कुचलने के बाद कई जगह बैरिकेडिंग तोड़कर भागा ट्रक ड्राइवर, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी

राजनांदगां। अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के गुंडरदेही गांव में सड़क किनारे खेल रही एक मासूम बच्ची को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ट्रक लेकर फरार हुआ और रोकने के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए भाग निकला। इसका वीडियो भी सामने आया है।

बच्ची की मौत के बाद गांव के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के थानों को अलर्ट किया और कई जगह बैरिकेडिंग कर ट्रक रोकने की कोशिश की।

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ट्रक नहीं रोका और तेज रफ्तार में बैरिकेड्स तोड़ते हुए निकल गया। इस दौरान बैरिकेड्स के पास तैनात पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। आरोपी ने एक नहीं बल्कि कई जगह लगातार पुलिस की घेराबंदी को तोड़ा और भागता रहा। पुलिस ने लगातार पीछा किया जिसके बाद ट्रक आखिरकार एक बैरिकैडिंग के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। इसके बाद कोरकोट्टी गांव के पास पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में चालक के नशे में होने की आशंका जताई गई है। उससे पूछताछ जारी है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। साथ ही सरकारी बैरिकेड्स तोड़ने और पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में छत्तीसगढ़ संपत्ति सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

धमतरी में आधी रात घर में घुसकर परिवार पर हमला

धमतरी। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में वाहन नहीं देने की मामूली बात पर जमकर मारपीट हो गई। नाराज आरोपियों ने एक महिला के घर में घुसकर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और तोड़फोड़ की गई। पुलिस से शिकायत करने के 24 घंटे के भीतर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम सेहराडाबरी निवासी प्रीति साहू ने शिकायत दर्ज कराई गई कि 23 जून की रात करीब 9 बजे उमेश साहू उसके घर वाहन मांगने आया था। वाहन देने से मना करने पर वह नाराज होकर लौट गया। इसके बाद उसी रात करीब 12 बजे उमेश साहू उर्फ छोटू, देवेंद्र साहू और प्रणेश मांडवी उर्फ प्रिंस एक राय होकर जबरन घर में घुस गए और अश्लील गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में प्रीति साहू, उनके पति मनोज साहू और पुत्री नीलिमा साहू घायल हो गए। आरोप है कि उमेश साहू ने लकड़ी के डंडे से हमला कर मनोज और नीलिमा को चोट पहुंचाई गई।

बिलासपुर निगम कर्मचारी से बदसलूकी की शिकायत

बिलासपुर। नगर पालिक निगम के स्वच्छता निरीक्षक पद पर कार्यरत टीम के साथ गाली-गलौज और अभद्रता का मामला सामने आया है। टीम के सदस्य पवन चौहान ने सिरगिट्टी और आजाक थाना सरकंडा में थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया है। इसमें कहा गया कि मुन्ना सिंह नाम के व्यक्ति ने उन्हें काम करने के दौरान धमकी दी और गाली-गलौज की। दरअसल शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ड्यूटी के दौरान निगम की स्वच्छता टीम शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन चेक कर रही थी। इसी दौरान तिफरा यदुनंदन नगर क्षेत्र स्थित एक किराना दुकान के संचालक के दुकान से प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई। इस दौरान दुकानदार ने अपने मकान मालिक से फोन पर बात कराई और मुन्ना सिंह नाम के व्यक्ति ने फोन पर उन्हें धमकी देकर गाली-गलौज की। इस दौरान प्रार्थी ने पूरी बातचीत अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और अधिकारियों को सूचना दी। साथ ही थाने पहुंचकर शिकायत की। आवेदन में आरोपी का नाम और मोबाइल नंबर का भी जिक्र किया है।

कोरबा में दो ट्रेलरों की भीषण टक्कर, जांच मु जुटी पुलिस

कोरबा। शनिवार की सुबह कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भालूमोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां दो तेज रफ्तार ट्रेलरों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह के समय हुआ जब दोनों ट्रेलर तेज गति से एक-दूसरे की ओर आ रहे थे। नियंत्रण खोने के कारण आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद एक ट्रेलर का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। शव केबिन के अंदर इस कदर फंस गया था कि उसे निकालने के लिए कटर का सहारा लेना पड़ा। दूसरा ट्रेलर चालक हादसे के बाद फरार हो गया। पुलिस अब फरार ट्रेलर और चालक की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ कर वाहन की पहचान की जा रही है। सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर कटर की मदद से ट्रेलर की केबिन काटी और चालक के शव को बाहर निकाला।

मनेंद्रगढ़ सिद्धबाबा धाम में आस्था का सैलाब

एमसीबी। जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र सिद्धबाबा धाम में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत शुक्रवार को भव्य शोभायात्रा निकाली गई। केदारनाथ धाम की तर्ज पर पुनर्निर्मित सिद्धबाबा धाम में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान भोलेनाथ के जयकारों और भजनों से पूरा शहर भक्तिमय नजर आया। शोभायात्रा श्याम मंदिर से विधि-विधान के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल और भरतपुर-सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो भी शामिल हुए। दोनों जनप्रतिनिधि बाबा के भजनों पर श्रद्धालुओं के साथ झूमते नजर आए। शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राम मंदिर पहुंची, जहां धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भगवान शंकर के त्रिशूल, भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदी महाराज एवं शिखर ध्वजा की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की गईं। इसके बाद शोभायात्रा झगराखांड़, नई लेदरी, खोंगापानी होते हुए सिद्धबाबा धाम पहुंची।

बीजापुर में आवारा कुत्तों के लिए बनेगा आधुनिक डॉग सेंटर

बीजापुर। बीजापुर मुख्यालय में अब आवारा कुत्तों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस डॉग सेंटर बनाया जा रहा है। भट्टीपारा तालाब के नीचे निर्माणाधीन इस केंद्र में एक समय में 100 कुत्तों को रखने की व्यवस्था होगी। यहां कुत्तों के लिए 2 एसी, 5 कूलर, 10 पंखे, भोजन और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नगरपालिका के सीएमओ बंशीलाल नुरुटी एवं डॉग सेंटर के नोडल अधिकारी व सहायक अभियंता देवेंद्र पहाड़ी ने बताया कि यह केंद्र केंद्र सरकार की एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना के तहत बनाया जा रहा है। इसके लिए 12 लाख 58 हजार रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य जिले के आवारा कुत्तों की संख्या को मानवीय तरीके नियंत्रित करना और रैबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम करना है। इसके तहत आवारा को पकड़ कर डॉग सेंटर लाया जाएगा, जहां उनका बधियाकरण एंटी रैबीज वेक्सिनेशन और पेट के कीड़ों का उपचार पशु चिकित्सको की निगरानी में किया जाएगा।

सुकमा जिले के जगरगुंडा स्थित शहीद के घर पहुंची मंत्री राजवाड़े

बोलीं- ऐसे परिवारों का सम्मान करना सरकार का नैतिक दायित्व

सुकमा। युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि उन घरों में भी हर दिन जारी रहता है, जहां किसी मां की आंखें अपने बेटे की राह ताकती रह जाती हैं। ऐसे ही दर्द, गर्व और त्याग से भरे माहौल के बीच मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सुकमा जिले के जगरगुंडा स्थित शहीद स्व्ह रामू राम नाग के निवास पहुंचीं। यह दौरा केवल एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि उस मां के दर्द को साझा करने का प्रयास था, जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बेटे को खो दिया। मंत्री राजवाड़े ने शहीद रामू राम नाग के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र की सुरक्षा एवं जनसेवा के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। घर का वातावरण भावुक था, जहां शहीद की यादें हर कोने में जीवंत दिखाई दे रही थीं। श्रद्धांजलि के बाद मंत्री राजवाड़े ने शहीद की माताजी से मुलाकात की। उन्होंने उनका हाथ थामकर हाल जाना और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवारों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद की माताजी के लिए अंत्योदय राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए। साथ ही उन्हें शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले। उन्होंने परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज विकास, विश्वास और शांति की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस परिवर्तन की मजबूत नींव उन वीर जवानों के बलिदान पर टिकी है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की।

बिन पानी का वार्ड गेल्हापानी, पानी की हर एक बूंद के लिए संघर्ष

एमसीबी। चिरमिरी नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 का गेल्हापानी है।लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि इस वार्ड में आज तक पानी की समस्या दूर नहीं हो पाई।यानी जैसा नाम वैसा काम नहीं हो सका। आज भी इस वार्ड में रहने वाली जनता पानी की हर एक बूंद के लिए संघर्ष कर रही है। आलम ये है कि घर की महिलाएं काम छोड़कर पानी जुगाड़ने में भिड़े रहते हैं।

टैंकर का इंतजार सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि स्कूल छोड़कर बच्चे भी करते हैं। इस वार्ड में पानी की सप्लाई एसईसीएल के माध्यम से की जाती है। लेकिन आए दिन मोटर खराब होने से पानी की सप्लाई बाधित होती है।गर्मी के समय समस्या और भी ज्यादा विकराल रुप ले लेती है। एक बार फिर एसईसीएल की ओर से मोटर खराब होने की सूचना स्थानीय लोगों को दी गई है।जिसके बाद लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चिरमिरी को नगर पालिका निगम बने लगभग 26 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में पीएचई की स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं पहुंच सकी। हर कुछ दिनों में मोटर खराब हो जाती है।

अस्थायी मरम्मत के बाद एक-दो दिन पानी आता है और फिर वही समस्या दोबारा खड़ी हो जाती है। महिलाओं का कहना है कि पानी की समस्या के कारण उनका पूरा दिन पानी जुटाने में निकल जाता है।कई बार बच्चों की पढ़ाई और घर के जरूरी काम तक प्रभावित हो जाते हैं। मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी रूपमती ने बताया कि एक सप्ताह से पानी नहीं आया है। मोटर बार-बार खराब हो जाती है। उषा की माने तो पूरा मोहल्ला पानी की समस्या से परेशान है। कई दिनों से नल में पानी नहीं आया है। बच्चों और परिवार के लिए दो से चार किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। स्कूल खुलने के बाद परेशानी और बढ़ जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

सक्ती गोलीकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने बनाई पांच सदस्यीय समिति

रायपुर। सक्ती जिले के ग्राम जोंगरा में गोली मारकर युवती पूर्णिमा चौहान की नकाबपोश युवकों द्वारा की गई हत्या के मामले की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर गठित इस समिति के संयोजक चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव को बनाए गए हैं। जांच समिति में जांजगीर-चांपा विधायक व्यास कश्यप, पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश, अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह और जैजेपुर विधायक बालेश्वर साहू को सदस्य बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समिति के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे पीड़ित परिवार और ग्रामवासियों से मुलाकात कर घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी लें। इसके बाद मामले की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे।

आज 35.98 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दो बूंद

रायपुर। देश भर में रविवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभियान के तहत राज्य के पांच वर्ष तक के 35 लाख 98 हजार 904 बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु दवा की दो बूंद पिलाई जाएगी। अभियान के संचालन हेतु 28,791 टीमों के साथ 57 हजार से अधिक वैक्सीनेटर तैनात किए गए हैं। बूथ दिवस के बाद 29 एवं 30 जून को टीमें घर-घर पहुंचकर ऐसे बच्चों को भी पोलियो की खुराक पिलाएंगी, जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाए। अभियान के सफल संचालन के लिए राज्य के सभी 33 जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला एवं विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित कर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और टीकाकरण दलों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। माइक्रोप्लान का सत्यापन, वैक्सीन की उपलब्धता, कोल्ड चेन प्रबंधन तथा आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

आषाढ़ के प्रथम दिवस पर 29 एवं 30 जून को होगा भव्य रामगढ़ महोत्सव

रायपुर। सरगुजा अंचल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत के प्रतीक रामगढ़ में आषाढ़ के प्रथम दिवस के अवसर पर 29 एवं 30 जून को दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतिष्ठित महोत्सव में प्रदेश की लोकसंस्कृति, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व और पर्यटन की समृद्ध विरासत एक साथ देखने को मिलेगी। महोत्सव के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल करेंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, इतिहासकार, कलाकार, शोधकर्ता, पर्यटक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहेंगे। 29 जून को प्रात: 10:30 बजे अतिथियों के आगमन एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। स्वागत समारोह, अतिथियों के उद्बोधन तथा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं पर आधारित लोकनृत्य, लोकगीत एवं लोकवाद्य प्रस्तुतियां पूरे दिन आकर्षण का केंद्र रहेंगी। सायंकाल सुप्रसिद्ध लोक एवं सांस्कृतिक कलाकारों की विशेष प्रस्तुतियां महोत्सव को और अधिक भव्य बनाएंगी। महोत्सव के दौरान आगंतुक विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीताबेंगरा गुफा, ऐतिहासिक जोगीमारा गुफा, रामगढ़ पर्वत श्रृंखला तथा अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण करेंगे। विशेषज्ञ इन धरोहरों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व की विस्तृत जानकारी देंगे।

केसरा उद्वहन सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 14.61 करोड़ रूपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा दुर्ग जिले के विकासखण्ड-पाटन की केसरा उद्वहन सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 14 करोड़ 61 लाख 33 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूरा हो जाने पर 1000 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। योजना के कार्यो को कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

रायपुर पहुंचे सोनू सूद का बड़ा बयान, राम मंदिर चंदा चोरी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

रायपुर। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे दुर्ग में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। रायपुर आगमन पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभिनेता ने गहरी निराशा जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। सोनू सूद कोरोना काल के बाद से ही अपनी सामाजिक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। आम जनता से सीधे जुड़े होने के कारण उनका बयान और गंभीर हो जाता है। राम मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है, ऐसे में चंदे में हुई इस कथित धोखाधड़ी को सोनू सूद ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है।

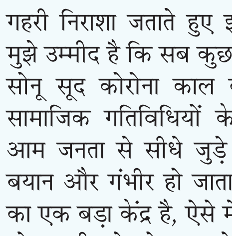

नवविकास की राह पर अग्रसर बस्तर, जगरगुण्डा पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री बनी राजवाड़े

कभी नक्सल प्रभाव का प्रतीक रहे इलाकों में अब विकास, विश्वास और जनभागीदारी की नई इबारत

रायपुर। बस्तर अब भय और हिंसा की पहचान से आगे बढ़कर विकास, विश्वास और जनसहभागिता के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। कभी नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहे सुदूर अंचलों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आजीविका के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसी परिवर्तनशील बस्तर की तस्वीर को और सशक्त करने महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े एक दिवसीय प्रवास पर सुकमा जिले के जगरगुंडा, चिंतलनार, पूर्वर्ती और सिलगेर पहुंचीं।

विशेष महत्व की बात यह रही कि श्रीमती राजवाड़े सड़क मार्ग से जगरगुंडा पहुंचने वाली पहली महिला मंत्री बनीं। वर्षों तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहे इस क्षेत्र में उनका आगमन विकास और शासन की संवेदनशील उपस्थिति का प्रतीक बनकर उभरा।

दौरे के दौरान मंत्री ने पूर्वर्ती एवं सिलगेर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया तथा अन्नप्राशन और गोदभराई कार्यक्रमों में शामिल होकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने बच्चों के साथ आत्मीय समय बिताया, ग्रामीण महिलाओं से संवाद किया और विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका अधिकाधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र कभी असुरक्षा और हिंसा के कारण चर्चा में रहते थे, वहीं आज महिला स्वावलंबन, शिक्षा, पोषण और सामाजिक विकास के केंद्र बन रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और नई संभावनाओं का सृजन कर रही हैं।

प्रवास के दौरान मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत जगरगुंडा स्थित कृतिका महिला संकुल स्तरीय संगठन (सीएलएफ) भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनकी आजीविका, स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

ग्रामीण महिलाओं ने इसे ऐतिहासिक

क्षण बताते हुए कहा कि पहली बार कोई महिला मंत्री सड़क मार्ग से सीधे जगरगुंडा पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनने और संवाद करने आई हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल शासन के प्रति उनके विश्वास को और मजबूत करने वाली है तथा यह अनुभव कराती है कि विकास की मुख्यधारा अब वास्तव में उनके गांव तक पहुंच चुकी है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर के अंतिम छोर तक विकास की रोशनी पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के साहस, स्थानीय जनसमर्थन और सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के समन्वित प्रयासों से बस्तर में शांति, स्थायित्व और समृद्धि का नया वातावरण निर्मित हुआ है। जगरगुंडा, पूर्वर्ती और सिलगेर जैसे क्षेत्रों में आज बच्चों की मुस्कान, महिलाओं का बढ़ता आत्मविश्वास और विकास की नई संभावनाएं बदलते बस्तर की सशक्त पहचान बन चुकी हैं।

मंत्री राजवाड़े ने शहीद एएसआई रामू नाग के निवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सुकमा जिले के जगरगुंडा स्थित शहीद एएसआई रामू राम नाग के निवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र की रक्षा एवं जनसेवा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने शहीद की माताजी से आत्मीय मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान प्रदेश और देश की अमूल्य धरोहर है तथा उनके परिवारों का सम्मान और संरक्षण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने संबंधित अधिकारियों को शहीद परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए शहीद की माताजी के लिए अंत्योदय राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने को कहा, ताकि उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सहजता से प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज विकास, विश्वास और शांति के नए युग की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में प्रदेश के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखना हम सभी का दायित्व है। शहीद परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

पुनर्वासित युवाओं से मिले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप

गांवों के विकास में सहभागी बनने का किया आह्वान, सिंचाई व्यवस्था के दिए निर्देश

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा नारायणपुर प्रवास के दौरान पुनर्वास केंद्र पहुंचकर हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा से जुड़े युवाओं से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने युवाओं से पुनर्वास केंद्र में मिल रही सुविधाओं, प्रशिक्षण और रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा की और उन्हें विकास की मुख्यधारा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने युवाओं से आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों और शासकीय सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य हर पुनर्वासित युवक-युवती को सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भर बनने के लिए सभी सुविधाएं देना है।

गृह मंत्री श्री शर्मा ने युवाओं से कहा कि वे जेल में बंद अपने पूर्व साथियों से मिलकर उन्हें भी पुनर्वास योजना का लाभ लेने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि विकास और शांति का रास्ता ही बस्तर के उज्ज्वल भविष्य का

आधार है।

उप मुख्यमंत्री ने केंद्र में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण की जानकारी ली। महिलाओं द्वारा मोटर वाहन ड्राइविंग का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में दिखाई जा रही भागीदारी की सराहना की।

चर्चा के दौरान युवाओं ने खेतों में सिंचाई के लिए बोर की जरूरत बताई। इस पर श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीदों के परिवारों और पुनर्वासित युवाओं का सर्वे कराकर उनके खेतों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि वे खेती से स्थायी आजीविका कमा सकें।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पेसा अधिनियम को और प्रभावी बनाने का काम लगातार हो रहा है। बस्तर के जनप्रतिनिधि आदिवासी समाज से हैं और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने को कहा। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहभागी बनने का आह्वान किया।

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर बस्तर के निर्माण तक आदिवासी समाज का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अब समय बस्तर को शांति, विकास और समृद्धि की नई दिशा देने का है। हिंसा छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने वाले युवाओं ने इस बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब सभी को मिलकर क्षेत्र और समाज के समग्र विकास के लिए काम करना चाहिए।

इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी., कलेक्टर कांकेर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर श्री रॉबिन्सन गुरिया सहित जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी तेज, एनसीएल बोर्ड का बड़ा फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी तेज छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में परियोजना के अगले चरण को मंजूरी देते हुए लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह कदम इस क्षेत्र में हीरे के वास्तविक भंडार का वैज्ञानिक आकलन करने और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

बैठक में निदेशक मंडल ने परियोजना की अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि के भीतर सभी तकनीकी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं। बड़े व्यास की ड्रिलिंग से किम्बरलाइट पाइप में मौजूद हीरा भंडार का सटीक आकलन किया जाएगा। इसके बाद विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (स्नद्गड्डह्यद्बढ्डद्बद्यद्बह्ल4 ऋद्गश्चश्रह्ल) तैयार होगी, जिसके आधार पर व्यावसायिक हीरा खदान विकसित करने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एनसीएल के निदेशक मंडल की बैठक में श्री अमिताभ मुखर्जी, श्री आशीष

चटर्जी, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, खनिज विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री रजत बंसल, श्री उपेंद्र कुमार तथा श्री विनय कुमार उपस्थित रहे।

एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड (51 प्रतिशत) तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (49 प्रतिशत) का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी अब तक लौह अयस्क परियोजनाओं पर केंद्रित रही है, लेकिन बलौदा-बेलमुंडी में प्राकृतिक हीरों की पुष्टि के बाद यह बहु-खनिज विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एनसीएल द्वारा स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और लक्षित ड्रिलिंग के माध्यम से किम्बरलाइट पाइप की पहचान की गई। इसके बाद लगभग 200 टन बल्क सैंपल का परीक्षण एनएमडीसी के पन्ना डायमंड प्रोसेसिंग प्लांट में किया गया, जहां 1.22 कैरेट वजन के पांच प्राकृतिक हीरे प्राप्त हुए।

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत

खाद खरीदने की टोकन व्यवस्था की गई खत्म प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक : कृषि मंत्री नेताम

रायपुर। खरीफ सीजन के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खाद वितरण की टोकन व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब राज्य के किसानों को खाद खरीदने के लिए पहले की तरह टोकन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे सहकारी समितियों और निर्धारित केंद्रों से अपनी जरूरत के अनुसार खाद प्राप्त कर सकेंगे।

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि राज्य में खाद का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। इसी को देखते हुए सरकार ने टोकन प्रणाली को खत्म करने का फैसला लिया है, ताकि किसानों को खाद लेने के लिए अनावश्यक इंतजार या बार-बार केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अब तक राज्य में किसानों को टोकन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से खाद उपलब्ध कराई जाती थी। इस व्यवस्था के तहत कई किसानों को तीन अलग-अलग टोकन के जरिए खाद लेनी पड़ती थी, जिससे समय और श्रम दोनों की अतिरिक्त जरूरत पड़ती थी।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसान एक ही बार में अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद खरीद सकेंगे। सरकार का कहना है कि राज्य में खाद का पर्याप्त भंडारण होने के कारण आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं है और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से खरीफ सीजन के दौरान खाद वितरण प्रक्रिया और अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक होगी, जिससे किसानों को खेती-किसानी के कार्यों में सहूलियत मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रेस-वार्ता में कहा-

नक्सल मुक्त बीजापुर अब विकसित बीजापुर की ओर बढ़ रहा

रायपुर। दो दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचीं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सल मुक्त बीजापुर अब विकसित बीजापुर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों से अब जिले में विकास का नया दौर शुरू हो चुका है और शासन की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने जिलेवासियों को सशस्त्र माओवाद से मुक्ति के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे बस्तर अंचल और देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में माओवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियान को बड़ी सफलता मिली है। अब बीजापुर सहित बस्तर संभाग शांति, सुरक्षा और विकास

के नए युग में प्रवेश कर रहा है।

प्रेस-वार्ता में मंत्री ने कहा कि वर्षों तक माओवादी गतिविधियों के कारण जिले के कई अंदरूनी क्षेत्रों तक विकास कार्य पूरी गति से नहीं पहुंच पाए थे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और शासन-प्रशासन पूरी क्षमता एवं प्रतिबद्धता के साथ उन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, संचार और अन्य आवश्यक सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाएगा, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी है। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का व्यापक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की व्यक्ति-मूलक योजनाओं से जिले के अंतिम व्यक्ति को जोड़कर समावेशी विकास का मॉडल तैयार किया जाएगा, जिससे हर परिवार विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन सके।

मंत्री ने कहा कि शांति और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। अब जब बीजापुर में शांति का वातावरण स्थापित हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को और गति मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का दायरा लगातार बढ़ेगा।

अर्जुन की तरह लक्ष्य साधेंगे, भाजपा को देंगे चुनौती : दीपक बैज

रायपुर। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर को लेकर जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। शिविर में संगठन को और मजबूत करने के साथ-साथ राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी ढंग से आवाज उठाने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है।

बैज ने कहा, प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा सकें। यह शिविर केवल संगठनात्मक मजबूती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अभी से रणनीति बनाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। बैज ने कहा, हमारे जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण के बाद अपने-अपने क्षेत्र में जाएंगे और अर्जुन की तरह लक्ष्य साधकर कौरव सेना का मजबूती से मुकाबला करेंगे। हमारा लक्ष्य मछली की आंख है, भाजपा के छल-प्रपंच से प्रदेशवासियों को दूर करना है।

वहीं प्रशिक्षण शिविर को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा था कि कांग्रेस नेता भांग पीकर प्रशिक्षण दे रहे हैं, बड़े नेता आते हैं और घुट्टी पिलाते हैं, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा की ट्रेनिंग देती है, गोडसे की विचारधारा की नहीं। अगर रामविचार नेताम कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में एक घंटे भी बैठ जाएं तो वे मंत्री पद से

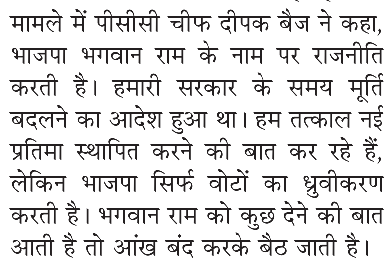

इस्तीफा दे देंगे और भाजपा छोड़ देंगे।

चंदखुरी में भगवान श्रीराम की नई प्रतिमा की स्थापना अब तक नहीं होने के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है। हमारी सरकार के समय मूर्ति बदलने का आदेश हुआ था। हम तत्काल नई प्रतिमा स्थापित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करती है। भगवान राम को कुछ देने की बात आती है तो आंख बंद करके बैठ जाती है।

सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में दीपक बैज ने कहा, हमारे आदिवासियों के बुढ़ादेव भगवान शिव हैं, धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया जा रहा है। यह भाजपा का षड्यंत्र है। दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में कानून-व्यवस्था फेल है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यूसीसी को लेकर डीसीएम विजय शर्मा के बयान पर दीपक बैज ने कहा, यूसीसी क्यों लाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत आदिवासी हैं। पेसा कानून और पांचवीं अनुसूची को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ।अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए यूसीसी लाया जा रहा है, क्या यह आदिवासियों के हित में है?

सक्ती गोलीकांड पर कांग्रेस की गठित जांच कमेटी को लेकर बैज ने कहा, ऐसा लग रहा है कि हम छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि यूपी-बिहार में हैं, जहां सरेराह गोलियां चलती हैं। सक्ती में एक युवती को नकाबपोश युवकों ने गोली मार दी। पीसीसी ने पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो पीड़ित परिवार से मिलेगा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हरसंभव मदद करेगा। बदहाल कानून-व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। खाद की कमी को और टोकन सिस्टम हटाए जाने को लेकर दीपक बैज ने कहा, किसानों और कांग्रेस की वजह से इन्हें नियम बदलना पड़ा। टोकन हटाना पड़ा, हम तो इसका विरोध कर ही रहे थे, लेकिन क्या टोकन हटा देने से समस्या हल हो जाएगी क्या ? अगर एक भी किसान आत्महत्या करता है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की अटकलें

राहिल नोरा चोपड़ा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलों को तेज कर दिया है। जहां भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी उत्तर प्रदेश इकाई में संगठनात्मक बदलाव की घोषणा की है, वहीं नए पदाधिकारियों की सूची को व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक संतुलन सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जून 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद से कोई विस्तार या फेरबदल नहीं हुआ है। इस संगठनात्मक फेरबदल पर बारीकी से नजर रखी जाएगी क्योंकि भाजपा 2027 के विधानसभा, राष्ट्रपति चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनावों सहित आगामी चुनावों की शृंखला के लिए तैयारी कर रही है। इस बात की संभावना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और भाजपा की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब जैसे आगामी चुनाव वाले राज्यों के नेता शामिल किए जा सकते हैं। केंद्रीय परिषद में अन्य जिन्हें बदला जा सकता है, उनमें सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल हैं। हालांकि वर्तमान रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को परिषद से नहीं हटाया गया है, जबकि उनका राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिट्टू को अपना कर्त्तव्य जारी रखने के लिए कहेंगे, जिनकी नजर अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों पर है। बिट्टू पंजाब के एक लोकप्रिय जाट सिख नेता हैं। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के वोट हासिल करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के हित केवल बसपा के साथ ही सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी सरकार के दौरान सभी वर्गों के लिए सम्मान और भागीदारी सुनिश्चित की है। 'एक्स' पर एक पोस्ट में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बसपा द्वारा उच्च जाति समुदायों, विशेषकर ब्राह्मणों के साथ जुडने और उन्हें चुनावों में प्रतिनिधित्व देने के कदम ने विपक्षी दलों के बीच 'बेचैनी' पैदा कर दी है। बसपा दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अपने पारंपरिक समर्थन आधार को मजबूत करने के साथ-साथ ब्राह्मणों तक अपनी पहुंच का विस्तार कर रही है। दूसरी ओर, सपा ने अपने मुख्य यादव-मुस्लिम आधार को प्रभावित किए बिना उच्च जाति के मतदाताओं तक अपनी पहुंच लगातार बढ़ाई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी ब्राह्मण सभा की एक बैठक आयोजित की और घोषणा की कि वह अगले साल के विधानसभा चुनावों के दौरान मजबूत ब्राह्मण चेहरों को बढ़ावा देंगे। उनसे बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने की उम्मीद है। बंगाल की पहली भाजपा सरकार राज्य में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) लागू करने के लिए एक विधेयक लाने की रणनीतिक योजना बना रही है। विधानसभा में आयोजित बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई और इसे अंतिम रूप दिया गया। इस बदलाव से राज्य में एक बड़ा कानूनी और सामाजिक नीतिगत बदलाव लाने की उम्मीद है, जिसमें भाजपा यू.सी.सी. को अपने प्रमुख शासन सुधारों में से एक के रूप में पेश कर रही है। भाजपा नेताओं के अनुसार, समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन पार्टी के संकल्प पत्र की प्रमुख प्रतिबद्धताओं में से एक था।

बदलने वाली है भारत की चीन पॉलिसी?

नीरज कुमार दुबे

सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की पूरी संभावना है जिसके चलते भारत चीन संबंधों में नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्ष 2020 से 2024 तक चले लंबे सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें अब अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई वार्ता ने यह संकेत दिया है कि दोनों देश सीमा विवाद के कम संवेदनशील हिस्सों में प्रारंभिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

हम आपको बता दें कि चीन की ओर से सीमा विवाद के अपेक्षाकृत कम विवादित क्षेत्रों, विशेषकर सिक्किम क्षेत्र में तथाकथित प्रारंभिक समझौते का प्रस्ताव रखा गया है। इसे सीमा निर्धारण प्रक्रिया में अर्ली हार्वेस्ट दृष्टिकोण माना जा रहा है। हालांकि भारत पहले इस प्रकार के चरणबद्ध समाधान का विरोध करता रहा है और उसका जोर पूरे सीमा विवाद के अंतिम और व्यापक समाधान पर था। वर्ष 2005 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते में भी यही कहा गया था कि सीमा विवाद का समाधान समग्र होना चाहिए। लेकिन अब बदलते भू-राजनीतिक वातावरण और हालिया तनावों के बाद नई दिल्ली भी अधिक व्यावहारिक नीति अपनाती दिखाई दे रही है।

इसके अलावा, नई दिल्ली में ब्रिक्स बैठक से इतर चीनी विदेश मंत्री वांग यी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने भी दोनों देशों के बीच संवाद प्रक्रिया को नई गति दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि बीजिंग भारत के साथ मिलकर आपसी विश्वास बढ़ाने, संदेह दूर करने और संवेदनशील मुद्दों को सावधानी से संभालने के लिए तैयार है। चीन ने यह भी दोहराया कि सीमा विवाद को दोनों देशों के व्यापक संबंधों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दूसरी ओर भारत लगातार यह कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य विकास के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता अनिवार्य है।

हम आपको यह भी बता दें कि दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई कार्य प्रणाली विकसित करने पर भी चर्चा हो रही है। यह व्यवस्था सीमा क्षेत्रों में तनाव कम करने, सैन्य गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और आकस्मिक टकराव रोकने के उद्देश्य से तैयार की जा सकती है। साथ ही भारत ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तर की वार्ता शीघ्र शुरू करने की मांग भी उठाई है। यह मुद्दा जल सुरक्षा, पर्यावरण और भविष्य की सामरिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।देखा जाये तो इन घटनाक्रमों का सामरिक महत्व बहुत व्यापक है। भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं और दोनों के बीच संबंधों का प्रभाव पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। वहीं चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध भी लगातार बढ़ता रहा है। यही कारण है कि नई दिल्ली अब ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसमें प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों साथ-साथ चल सकें।साथ ही अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में यह तर्क भी तेजी से उभर रहा है कि भारत को जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। जापान अमेरिका का प्रमुख सुरक्षा सहयोगी होने के बावजूद चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाए रखता है। दोनों देशों के बीच समुद्री विवाद और राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन टोक्यो ने कभी चीन के साथ आर्थिक संपर्क पूरी तरह समाप्त नहीं किया। जापान ने सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अलग स्तर पर संभालने की नीति अपनाई है। भारत के लिए भी यह मॉडल उपयोगी माना जा रहा है।

दक्षिण कोरिया का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। सियोल अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था चीन के विशाल बाजार से गहराई से जुड़ी हुई है। थाड मिसाइल प्रणाली को लेकर चीन और दक्षिण कोरिया के बीच गंभीर तनाव पैदा हुआ था, फिर भी सियोल ने संबंध समाप्त करने की बजाय संतुलित नीति अपनाई। उसने आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने के साथ संवाद बनाए रखा। भारत भी अब वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध अत्यंत व्यापक है। ऐसे में पूर्ण टकराव की नीति भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकती है।

रणनीतिक दृष्टि से देखें तो भारत अब बहु संतुलन वाली विदेश नीति की ओर बढ़ रहा है। एक ओर वह अमेरिका के साथ रक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ तनाव प्रबंधन और आर्थिक संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह नीति भारत को अधिक सामरिक स्वायत्तता प्रदान कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत चीन संबंधों में स्थिरता आती है तो इससे नई दिल्ली को वैश्विक स्तर पर अधिक स्वतंत्र कूटनीतिक भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।भारत और चीन दोनों प्राचीन सभ्यताएं, विशाल बाजार और उभरती वैश्विक शक्तियां हैं। दोनों देशों की संयुक्त आबादी विश्व की लगभग एक तिहाई है। ऐसे में निरंतर शत्रुता न केवल एशिया की स्थिरता के लिए चुनौती होगी, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करेगी। यही कारण है कि दोनों देश अब सीमित सहयोग, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और निरंतर संवाद की नीति पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।बहरहाल, सीमा विवाद, आपसी अविश्वास और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन हालिया कूटनीतिक गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि नई दिल्ली और बीजिंग संबंधों को टकराव के बजाय स्थिरता की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह प्रक्रिया सफल होती है तो इससे न केवल एशिया में शक्ति संतुलन मजबूत होगा, बल्कि भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

वेदादि शास्त्रों के आयुष्य-विषयक समस्त वर्णनों की एकवाक्यता की जाय तो हमें चार प्रकार की जीवन सीमा उपलब्ध होती है यथा -

(1) अमर- कुछ ऐसे प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं. कि जिससे बहुत से जीवनधारियों का अमर होना पाया जाता है। ये जरा पलित आदि से उन्मुक्त रहते हुवे दिव्य आयु का उपभोग करते हैं, जैसे देवता, दिव्य पितर यौर देहाध्यासरहित योगीश्वर आदि ।

(2) चिरंजीवी- दूसरे कुछ ऐसे भी प्राणधारी हैं जो कि अमर पद के अधिकारी तो न हो सके परन्तु अपेक्षाकृत उनकी आयु अतीव दीर्घ होती है। इससे वे एक लम्बी- किन्तु अनिश्चित अवधि तक - यथेच्छ विचरते रहते हैं। जैसे श्रश्वत्थामा, बली, व्यास और हनुमान् आदि।

(3) स्वच्छन्द मृत्यु- तीसरे वे प्राणी हैं जिन्होंने कि स्वयं ब्रह्मचर्य्यादि को धारण करके अथवा योगाभ्यासपूर्वक जीवन बिता कर मृत्यु के ऊपर अपना अधिकार कर लिया हो- तदनुसार वे जब चाहें तब अपने जराजीर्ण शरीर का परित्याग करें। जैसे भीष्मपितामह, युधिष्ठिरादि पाण्डव आदि ।

(4) सर्वसाधारण- जो किसी प्रकार की योग्यता नहीं रखते वे जिस हद्द तक संयत जीवन बितायेंगे उतनी ही अधिक आयु को प्राप्त होंगे, और जितने उत्पथ-गामी होंगे उतनी ही जल्दी मरेंगे, जैसे सदाचारी और दुराचारी।

वेदोक्त आयुष्यवाद

ऊपर जो आयुष्य के चार भेद प्रकट किए गये हैं अब उनका वेद-प्रमाणों से समर्थन किया जाता है, यथा-

(क) प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा धर्मणाहँ कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च । जरदष्टिः कृतवीर्यो विहायाः सहस्रायुः सुकृतश्चरेयम् ।(अथर्व 17 ।1 ।27)

क्रमशः ...

भारत की राजनीति के चाणक्य थे पीवी नरसिम्हा राव

अनन्या मिश्रा

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का आज ही के दिन यानी की 28 जून को जन्म हुआ था। देश में आर्थिक सुधारों का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। क्योंकि उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार और आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे। उनको भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था।

आंध्र प्रदेश के करीमनगर में 28 जून 1921 को पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी शुरूआती शिक्षा पूरी करने के बाद हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पीवी नरसिम्हा राव ने बतौर वकील अपने करियर की शुरूआत की, लेकिन

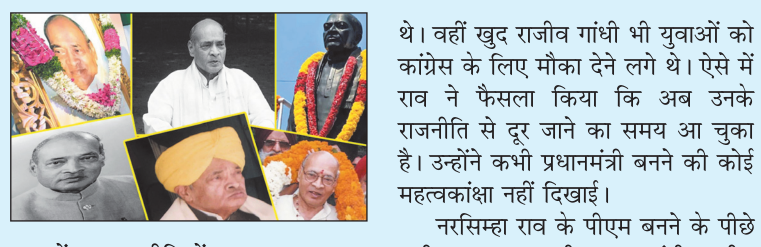

बाद में वह राजनीति में आए। साल 1962 से 1964 तक आंध्र प्रदेश में वह कानून और सूचना मंत्री फिर साल 1967 तक कानून और विधि मंत्री, फिर 1967 में स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। वहीं साल 1971 से लेकर 1973 तक वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। साल 1975 से 1976 तक वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव पद पर रहे।

बता दें कि साल 1991 के चुनाव से पहले नरसिम्हा राव 69 साल के हो चुके थे। वहीं खुद राजीव गांधी भी युवाओं को कांग्रेस के लिए मौका देने लगे थे। ऐसे में राव ने फैसला किया कि अब उनके राजनीति से दूर जाने का समय आ चुका है। उन्होंने कभी प्रधानमंत्री बनने की कोई महत्वकांक्षा नहीं दिखाई।

नरसिम्हा राव के पीएम बनने के पीछे बड़ी वजह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की असमय मौत बताई गई थी। इस घटना ने न सिर्फ देश बल्कि चुनाव की भी तस्वीर बदल गई। जहां राजीव गांधी की मौत से पहले भाजपा और कांग्रेस में टक्कर चल रही थी, तो वहीं इस हादसे के बाद कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर दौड़ गई और लोकसभा में 232 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह सरकार बनाने में सक्षम थी। अब कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट था। राजीव गांधी के बच्चे छोटे थे और सोनिया गांधी राजनीति में आना नहीं चाहती थीं।

ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर सर्वानुमति पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर मुहर लगी और वह देश के 9वें प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने बतौर पीएम पार्टी के अंदर चल रही गतिरोधों को संभाला। लेकिन इसके कारण नरसिम्हा राव के विरोधी बढ़ते गए। वहीं अर्जुन सिंह और शरद पराव जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन फिर भी नरसिम्हा राव की सरकार ने पांच साल पूरे किए।

पीएम नरसिम्हा राव का कार्यकाल कई बदलावों का गवाह रहा। फिर चाहे वह साल 1991 में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्तमंत्री बनाकर देश में निजीकरण करना हो, या बाबर मस्जिद ढांचा ढहाए जाने का विवाद हो।

आंतरिक और बाहरी दबावों के आगे झुका अमेरिका

शशांक

फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान युद्धविराम समझौते पर अमेरिका और ईरान के हस्ताक्षर होने के तत्काल बाद स्विट्जरलैंड में अगले दौर की वार्ता में भी दोनों के बीच जिस तरह कुछ सहमति बनती दिख रही है, उससे दुनिया ने राहत की सांस ली है। फ्रांस में चौदह बिंदुओं वाले जिस समझौते पर दोनों पक्षों ने दस्तखत किये, उसमें हर मोर्चे पर संघर्ष का अंत, दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश, अमेरिका द्वारा 30 दिनों के भीतर नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह समाप्त करना, होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए धन, ईरान पर लगे प्रतिबंध समाप्त होना, ईरान द्वारा परमाणु क्षमता हासिल नहीं करना, संवर्धित यूरेनियम का समाधान होने तक परमाणु कार्यक्रम यथास्थिति में बनाये रखना और इस दौरान तेल व पेट्रोलियम उत्पादों और उनसे जुड़ी सेवाओं के लिए ईरान को छूट मिलना, ईरान की फ्रीज हुई संपत्ति रिलीज करना आदि शामिल हैं। इस बीच अमेरिका ने ईरानी तेल पर लागू प्रतिबंध को आगामी अगस्त तक हटा लिया है।

समझौते में पाकिस्तान की भूमिका अहम रही है और लेबनान को समझौते में शामिल करने की उसकी बात भी मानी गयी है। हालांकि, समझौते में इस्राइल शामिल नहीं है। लेबनान को समझौते में शामिल करना ईरान के लिए संतोष की बात होनी चाहिए। संतोष की दूसरी बात यह है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जिस तरीके से सैकड़ों जहाज रुके हुए थे, उनकी आवाजाही फिर शुरू हो जायेगी। हालांकि इसमें अभी 30 दिन का समय तो लगेगा ही। पर इतना तो तय है कि बीते कई महीनों से जो अनिश्चितता बनी हुई थी, वह अब समाप्त हो गयी है। अब चूंकि समझौता हो गया है, तो इसे बनाये रखने के लिए भारत, चीन, रूस समेत नाटो के सदस्यों को

सक्रियता दिखाते हुए पश्चिम एशिया में सुरक्षा और शांति पर ध्यान देना होगा, ताकि समझौते की शर्तों का उल्लंघन न हो।

पश्चिम एशिया में शांति बहाली की जिम्मेदारी केवल पाकिस्तान या अमेरिका, ईरान और इस्राइल पर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि बाकी के देशों को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि युद्धविराम का यह जो अवसर मिला है, उससे क्षेत्र में दीर्घकालिक व स्थायी शांति स्थापना की राह बन सके। यहां कतर की चर्चा भी जरूरी है। भले ही सीधे तौर पर कतर इस समझौते में शामिल नहीं रहा है, पर शांति के लिए प्रयासरत तो रहा ही है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी तरफ से अमेरिका और ईरान को यह आश्वासन देने की कोशिश जरूर की है कि अपने सैन्य अड्डे का इस्तेमाल वह ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देगा, इसलिए ईरान कतर पर हमला न करे। वैसे भी कतर और ईरान के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। वहीं, इस्लामाबाद सऊदी अरब से अपने अच्छे संबंध का हवाला देते हुए संभवतः सऊदी अरब और ईरान, दोनों को यह समझाने में सफल रहा है कि सऊदी के सैन्य अड्डे ईरान के खिलाफ उपयोग में नहीं लाये जायेंगे।

अब, जब मसला सुलझ रहा है, तब यह सवाल उठता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया था। तो उसके कई कारण थे। पहली बात, वह ईरान में सत्ता बदलना चाहता था। दूसरी, वह उसके यूरेनियम भंडार समाप्त कर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता था। तीसरी, वह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता था और चौथी बात, वह ईरान की नीतियों में बदलाव कर वहां किसी ऐसी सरकार को बिठाना चाहता था, जिसके जरिये ईरान अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हो जाये। इनमें से किसी भी मामले में अमेरिका को सफलता नहीं मिली है। जहां तक इस्राइल की बात है, तो कहा जा सकता है कि वह यहां अलग-थलग पड़ गया है।

असल में ट्रंप द्वारा समझौता करने से इस्राइल की सरकार खुश नहीं है। हालांकि, अमेरिका समय-समय पर इस्राइल को सूचित करता रहा है। फिर भी यहां एकतरफा संवाद ही रहा है और इस बार इस्राइल की बात नहीं मानी गयी है। जबकि ट्रंप ने जिस तरह अपनी निजी जिम्मेदारी समझते हुए पश्चिम एशिया में शांति बहाली के प्रयास किये, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। समझौते के तहत ईरान को उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने और पुनर्निर्माण के लिए धन दिया जाना है। समझौते की यह शर्त काफी व्यावहारिक है, क्योंकि ईरान बुरे दौर से गुजर रहा है। युद्धविराम समझौते के जरिये इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होने की उम्मीद बंधी है। यहां ईरान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह हिज्बुल्ला को समझाये कि वह इस्राइल पर हमला बंद करे। दूसरी ओर ट्रंप को इस्राइली सरकार को समझाना होगा कि वह लेबनान पर हमला बंद करे और क्षेत्र में शांति लाने का प्रयास करे।

यहां इस बात का जिक्र भी आवश्यक है कि आखिर किस तरह यह समझौता हो पाया, क्योंकि पिछले काफी समय से दोनों देशों के बीच बात बनते-बनते रह जाती थी। अमेरिका की बात करें, तो युद्ध के कारण डेमोक्रेट्स तो उनसे नाराज थे ही, 'मागा' ('मेक अमेरिका ग्रेट अगेन') के उनके जो समर्थक हैं, उनमें से भी 20-30 प्रतिशत उनसे दूर हो गये थे और कुछ उनके विरोध में आ गये थे। ईरान पर हमले से अमेरिका की लिबरल-डेमोक्रेटिक छवि को भी नुकसान पहुंच रहा था। एक और कारण खाड़ी के देशों का अमेरिका पर दबाव था कि वह क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए कदम उठाये, क्योंकि इन देशों ने अरबों खर्च कर अपनी सुरक्षा और शांति के लिए अपने यहां अमेरिकी सैन्य अड्डे बनाये हैं, पर ईरान ने उन्हें निशाना बनाया और नष्ट कर डाला। ऐसे में इन देशों में यह धारणा बनने लगी थी कि अमेरिका जब अपने आपको ही नहीं बचा सका, तो उन्हें क्या बचायेगा। ईरान की बात करें, तो उसके लगभग सारे नेता युद्ध में मारे जा चुके थे और जो नये नेता थे, वे छिपकर बैठे थे। ईरान इस गतिरोध से बाहर निकलना चाहता था। फिर ईरान की सत्ता ने जिस तरह अपने आलोचकों को मार डाला, उसे लेकर भी वहां के लोगों के मन में रोष था। तीसरी बात, ईरान के कूटनीतिक वार्ताकार इस कोशिश में लगे हुए थे कि शांति की दिशा में चल रही बातचीत सफल हो जाये। उधर आइआरजीसी के युवा अधिकारियों को भी समझ में आने लगा था कि युद्ध से ईरान को कोई लाभ नहीं होने वाला है। उल्टे इससे ईरान समेत पूरा क्षेत्र तबाह हो जायेगा। अंत में, हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि समझौते से किसकी जीत हुई है और किसकी हार। बड़ी बात यह है कि शांति समझौते से मानवता की जीत हुई है।

आज का इतिहास

1838 ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में की गयी।

1841 फ्रेंच संगीतकार एडोल्फ एडम के एक बैले गिस्ले को पेरिस के थिएटर डे ल आकडेमी रोयाले डे मस्किक में पहले स्थान पर रखा गया था।

1846 बेल्जियम के शहनाई वादक एडोल्फ सैक्स को सैक्सोफोन के लिए पेटेंट मिला।

1880 विक्टोरिया के ग्लेनरोवन में बंदूक की लड़ाई के बाद पुलिस ने ऑस्ट्रेलियाई बैंक लुटेरा और सांस्कृतिक आइकन नेडकेली को पकड़ लिया।

1883 इटली के मिलान में पहला यूरोपीय केंद्रीय बिजली पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया।

1884 महिलाओं के अधिकार के लिए नार्वे एसोसिएशन की स्थापना की गयी।

1895 अल सल्वाडोर, होंडुरास और निकारागुआ मध्य अमेरिकी यूनियन का गठन किया गया।

1895 यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ़ प्राइवेट लैंड क्लेम ने फैसला सुनाया कि जेम्स रेविस ने 18,600 वर्ग मील (48,000 किमी 2) इन-डे-डे एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको द्वारा दावा किया था कि पूरी तरह से काल्पनिक और कपटी था।

1922 आयरिश सिविल वॉर की शुरुआत आयरिश फ्री स्टेट की नेशनल आर्मी द्वारा फोर कोर्ट्स बिल्डिंग पर हमले के साथ हुई थी, जिस पर एंटी-ट्रीटी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने कब्जा कर लिया था।

1926 गोतलिब डेमलर और कार्ल बेंज ने कंपनियों को मिलाकर मर्सिडीज-बेंज की स्थापना की।

1942 द्वितीय विश्व युद्ध-जर्मन वेहरमैच ने केस ब्लू लॉन्च किया, सोवियत संघ को अलवर से बाहर खदेड़ने के लिए आक्रामक गर्मियों की शुरुआत की।

1972 अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोषणा की, कि वियतनाम को कोई नया प्रारूप नहीं भेजा जाएगा।

1976 अमेरिका के एयरफोर्स एकेडमी में पहली महिला का प्रवेश हुआ।

1981 तेहरान में पार्टी के मुख्यालय में बम विस्फोट होने पर ईरान के इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के तीन प्रमुख अधिकारियों की हत्या कर दी गई।

1989 सर्बिया के राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोएविच ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने सेर्बिया के राष्ट्रीय विकास के भविष्य में सशस्त्र लड़ाई की संभावना का वर्णन किया।

बिगड़ती ही जा रही है महाविकास आघाड़ी की गाड़ी

अमिताभ श्रीवास्तव

अभी शिवसेना ठाकरे गुट के सांसदों के टूटने की खबरें कम नहीं हुई थीं कि महाविकास आघाड़ी की बैठक में 23 विधायकों की अनुपस्थिति चर्चा में आ गई है। इसकी गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई, क्योंकि बैठक का आयोजन हाल की गतिविधियों को देख कर किया गया था। यह समझा जा रहा है कि सांसदों के बाद अब विधायकों पर डोरे डालने की कोशिश जारी है। हालांकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) का पतन पूरी तौर पर थमा हुआ है। उसके नेताओं को अपने सांसदों और विधायकों पर विश्वास है। किंतु शिवसेना का शिंदे गुट किसी भी कीमत पर ठाकरे गुट को चैन से बैठने नहीं दे रहा है। वह लगातार अपनी ताकत बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दबाव बनाए रखना चाहता है।

दरअसल महागठबंधन के दोनों दल भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट अपनी-अपनी पार्टी की गतिविधियों को लेकर एक-दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे आपस में कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन वर्ष 2019 में गठित महाविकास आघाड़ी में आरंभ से ही यह भावना रही है कि तीनों दल परस्पर हितों को ध्यान रखेंगे और मुसीबत के साथी बने रहेंगे। भाजपा के खिलाफ बनी यह रणनीति इन दिनों कमजोर होती दिख रही है, जो शिवसेना के ठाकरे गुट के लिए सबसे अधिक चिंता का कारण है। वह अपनी परेशानी में आघाड़ी का नैतिक समर्थन बनाए रखना चाहता है। बीते बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के बीच राज्य के मुख्य विपक्ष महाविकास आघाड़ी ने मुंबई में अपने विधायकों की एक विशेष बैठक बुलाई थी, जिसके अप्रत्यक्ष रूप से आयोजक शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ही थे।

बैठक का कागजी उद्देश्य विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाने, सदन के अंदर और बाहर एकजुट रुख अपनाने और सभी सहयोगी पार्टियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना था। मगर मन की बात यही थी कि राज्य में तोड़-फोड़ की राजनीति से कैसे निपटा और एक-दूसरे का सहारा किस प्रकार बना जाए। किंतु विपक्षी आघाड़ी की पार्टियों के कुल 60 विधायकों में से सिर्फ 37 बैठक में शामिल हुए। जिसमें शिवसेना ठाकरे गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के साथ-साथ संजय राऊत, शशिकांत शिंदे और सतेज

पाटिल मौजूद थे। वहीं, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, विश्वजीत कदम, अमित देशमुख, रोहित पवार, अभिजीत पाटील, विकास ठाकरे, संदीप क्षीरसागर, जयंत पाटिल जैसे नेता अनुपस्थित थे। इससे पहले शिवसेना ठाकरे गुट की अपनी बैठक में चार विधायक अनुपस्थित थे और आघाड़ी की ताजा बैठक में पार्टी के पांच विधायक नहीं पहुंचे। जिससे माना गया कि उद्धव ठाकरे की चिंताओं पर बुलाई गई बैठक का नतीजा अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं मिलने के रूप में आया।

परिस्थिति को देख यह भी अंदाज लगा कि शिवसेना के उद्धव गुट की बिगड़ती स्थिति से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कहीं न कहीं दूरी बना ली है। इससे सिद्ध हुआ कि जहां विचार आगे की लड़ाई पर ध्यान देने के लिए होना था, वहां आघाड़ी को एकजुट रखना ही मुश्किल साबित हो रहा है। कहा यह गया कि बैठक में गठबंधन के भीतर तालमेल और उसकी संगठनात्मक ताकत पर चर्चा हुई। विधायकों की अनुपस्थिति रेखांकित हुई। परंतु अंदर की वास्तविकता पहले ही बाहर आ गई।

महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए दो साल बीत चुके हैं और कुछ माह में विधानसभा के कार्यकाल का दूसरा साल पूरा होने जा रहा है। आगे के दो वर्ष के अवसर के बाद आखिरी चुनावी साल में बदल जाएगा। यही चिंता सांसदों और विधायकों की है। जिन्हें अपने-अपने नेतृत्व से न तो विकास के लिए कोई दिशा मिल रही है और न ही लड़ने के लिए हिम्मत दिलाई जा रही। चुनाव के समय की एकजुटता जमीनी संघर्ष के अवसरों पर नहीं बनी रहती है।

आघाड़ी के तीनों दल अपनी-अपनी दिशा में भागते हैं। जिसके चलते हर सांसद-विधायक को निजी स्तर पर प्रयास कर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ रहा है। इसी स्थिति का चारों ओर से लाभ सत्ताधारी दल उठा रहे हैं। वे विपक्षी सांसदों और विधायकों को बार-बार इस बात का अनुभव करा रहे हैं कि उनका नेतृत्व कमजोर है। वह उनकी लड़ाई आगे नहीं ले जा सकता है। इसलिए या तो वे उनके दल में शामिल हों या फिर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उनका समर्थन करें। कोरोना महामारी को बीते छह साल हो गए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष बार-बार 'फेसबुक लाइव' का ताना मारकर विपक्ष की नेतृत्व क्षमताओं पर उंगली उठाता रहता है। जिसका पुरजोर उत्तर सामने नहीं आता है। केवल नेताओं के पार्टी छोड़ने पर ही सक्रियता दिखती है, जो गाली-गलौज की सीमा तक जा पहुंची है। इस स्थिति में आघाड़ी के भविष्य पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।

करीब सात साल पहले जब महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ था, तब शरद पवार, नाना पटोले, संजय राऊत, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, विजय वडेट्टीवार जैसे नेता अग्रिम मोर्चे पर थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे को केवल नेतृत्व ही नहीं, बल्कि एकजुटता का बल दिया था। उस समय उम्मीद थी कि शिवसेना की दी शक्ति भाजपा के लिए चुनौती बनेगी। किंतु ढाई साल में ही शिवसेना का किला ढहने लगा। जिससे उसके भविष्य को लेकर अनेक चिंताओं को जन्म मिल गया। इस बीच, राकांपा में भी फूट हुई, लेकिन वह 'जानी-दुश्मनी' में नहीं बदली। कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं आया। विधानसभा चुनाव के बाद अनेक स्थानीय स्तर के चुनावों में कांग्रेस और राकांपा के मतदान में विशेष अंतर नहीं देखा गया। दोनों दलों ने स्थानीय निकायों को अपने दम पर हासिल किया।

वहीं, शिवसेना के पदाधिकारी इधर-उधर भागते रहे। यही वजह है कि आज बदले परिदृश्य में आघाड़ी को लगातार मजबूत रखना मुश्किल हो रहा है। शिवसेना के ठाकरे गुट के लगातार पतन के बीच दूसरे सहयोगियों को भविष्य में एकजुटता का कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। इससे स्पष्ट है कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी तभी चल सकती है, जब सभी दल संगठनात्मक रूप से एकजुटता के साथ काम करें। जैसा कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। बस आने वाले दिनों में आघाड़ी के साथ कहीं ऐसा न हो।

समग्र हिंदुत्व की राह पर भाजपा

मृत्युंजय दीक्षित

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में सभी राजनैतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियों और मुद्दों को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। माना जा रहा है कि भाजपा की यह टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नेतृत्व की पसंद से चुनी गई है किन्तु इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी महती भूमिका है। भाजपा ने अपनी नई टीम में सामाजिक सन्तुलन साधने के साथ ही सपा के पीडीए व बसपा के ब्राह्मण कार्ड को रोकने का प्रबंध किया है। अब चुनाव केवल सामाजिक समीकरण के बल पर ही नहीं जीते जाते इसलिए भाजपा ने अपनी टीम की संरचना से यह भी स्पष्ट किया है कि वह चुनावी दंगल बूथ स्तर पर आकर ही लड़ेगी। भाजपा अब अपने बूथ प्रबंधन को सशक्त करने के लिए काम करेगी जिसके लिए प्रदेश की टीम को एकदम युवा व कर्मठ चेहरे दिए गए हैं। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रवक्ताओं की टीम भी घोषित कर दी गई है और सोशल मीडिया प्रमुख की भी नियुक्ति की गई है क्योंकि अब प्रमुख राजनैतिक नैरेटिव युद्ध पारंपरिक और सोशल मीडिया दोनों पर लड़ा जाता है। चुनावी जंग जीतने में मीडिया व सोशल मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल चुनावों में नैरेटिव युद्ध ने भाजपा की विजय में बड़ी भूमिका निभाई थी।

भाजपा की नई कार्यकारिणी से यह बात भी साफ हो गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे व हिंदुत्व की धर तेज करके ही लड़ा जाएगा। प्रदेश में योगी जी का एक रहेंगे तो नेक रहेंगे तथा बटेंगे तो कटेंगे का नारा फिर चलने वाला है। प्रदेश के आम हिन्दू जनमानस को योगी जी पर पूरा भरोसा है विशेषकर कानून व्यवस्था व नारी सुरक्षा आदि विषयों के कारण।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में सपा के पीडीए की धार कुंद करने का प्रयास किया गया है। राज्य में भाजपा का संगठन 6 क्षेत्रों में विभाजित है। इनमें पश्चिम नवाब सिंह नागर को, ब्रज क्षेत्र में पूरन लाल लोधी तथा कानपुर क्षेत्र में राम किशोर साहू अध्यक्ष बने हैं। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया बनाए गए हैं। अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी बने हैं। गोरखपुर क्षेत्र की कमान विनोद राय को मिली है जो भूमिहार हैं। प्रदेश में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इनमें भी ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। 8 महामंत्रियों की सूची मे भी 4 ओबीसी वर्ग के हैं।

प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के चयन में सामाजिक संतुलन के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास भी किया गया है। सपा छोड़कर भापजा मे शामिल हुई पूजा पाल को प्रयागराज में जिम्मेदार दी गई है। एक समय प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का आतंक था और उस पर पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या का आरोप था। भाजपा ने अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से दलित गैर-जाटव समुदाय से पासी और कोरी समाज को भी साधने का प्रयास किया है। भाजपा ने कुशवाहा, मौर्य और सैनी समुदाय से तीन नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है जाट, कुर्मी, यादव और पाल समाज से भी उपाध्यक्ष बनाया गया ।

भाजपा की कार्यकारिणी से प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के तरकश में अभी कई तीर छिपे हैं। यह बात तो तय हो गई है कि अब भाजपा समग्र हिंदुत्व की राजनीति करने जा रही है। भाजपा व संघ द्वारा अब प्रदेश में बंगाल की ही तरह 94 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा।

भाजपा कार्यकारिणी की सूची आते ही सपा, बसपा व कांग्रेस की राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई है। यह चर्चा भी सुनी जा रही है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के चुनाव वर्ष 2026 के अक्टूबर- नवंबर में भी करवा सकता है क्योंकि आगे जनगणना का वृहद अभियान चलना है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल तथा असम सहित कई राज्यों के निकाय चुनावों में लगातार मिल रही सफलता से उत्साहित है और अपनी विजय का संवेग बनाए रखने के लिए के लिए विपक्ष को तैयारी के लिए समय नहीं देना चाहती।

बड़ा मिशन लेकर सेशेल्स जा रहे हैं मोदी

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 से 29 जून तक होने वाली सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक सक्रियता और वैश्विक भूमिका को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में मोदी की भागीदारी यह संकेत देती है कि भारत अब हिंद महासागर में अपने मित्र देशों के साथ सुरक्षा, विकास और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

हम आपको बता दें कि सेशेल्स 115 द्वीपों वाला छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मोजाम्बिक चैनल के निकट उन समुद्री मार्गों पर स्थित है, जहां से विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसी कारण अमेरिका, चीन और यूरोपीय शक्तियां भी इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे समय में भारत का सेशेल्स के साथ संबंध मजबूत करना हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भारत द्वारा सेशेल्स तटरक्षक बल को एक तीव्र गश्ती पोत सौंपना है। इससे पहले भारत दो डोर्नियर विमान, कई गश्ती नौकाएं तथा तटीय निगरानी राडार प्रणाली भी सेशेल्स को प्रदान कर चुका है। भारतीय रक्षा कर्मियों की तैनाती और संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने दोनों देशों के रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दी है। समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सेशेल्स भारत पर भरोसा करता है। यही कारण है कि यह यात्रा हिंद महासागर में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।

हम आपको बता दें कि भारत की महासागर दृष्टि के अंतर्गत सेशेल्स को विशेष स्थान प्राप्त है। भारत अब केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहना

चाहता, बल्कि वह पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार की भूमिका निभा रहा है। सेशेल्स का कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में पूर्ण सदस्य बनने का संकेत भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस समूह में भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका पहले से शामिल हैं। यदि सेशेल्स भी पूर्ण सदस्य बनता है, तो हिंद महासागर में भारत के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और मजबूत होगी।

हम आपको बता दें कि मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच होने वाली वार्ता में रक्षा सहयोग के साथ ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल शासन, समुद्री निगरानी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। फरवरी 2026 में भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें ऋण सहायता और अनुदान दोनों शामिल हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सौर ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। यह दर्शाता है कि भारत केवल सामरिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विकास साझेदारी के माध्यम से भी अपने मित्र देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध बना रहा है।

हम आपको बता दें कि भारत और सेशेल्स के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरे हैं। वर्ष 1770 में भारतीयों का पहला समूह वहां पहुंचा था। आज लगभग 15 हजार भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं। गुजराती और तमिल समुदाय व्यापार, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोदी का भारतीय समुदाय से संवाद दोनों देशों के सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेगा।

यह यात्रा वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव का तेजी से विस्तार किया है। चीन की समुद्री परियोजनाएं, बंदरगाह निवेश और सामरिक उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं। ऐसे में सेशेल्स जैसे देशों के साथ भारत का गहरा सहयोग यह स्पष्ट संदेश देता है कि हिंद महासागर में भारत अपनी पारंपरिक भूमिका को और सशक्त बना रहा है। भारत की नीति अब केवल पड़ोसी प्रथम तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभरना चाहता है। सेशेल्स यात्रा इसी व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा है।

इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा के विशेष अधिवेशन को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। यह दोनों देशों के राजनीतिक विश्वास और घनिष्ठता का प्रतीक माना जा रहा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और रक्षा दल की भागीदारी भी यह दिखाती है कि दोनों देशों के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर में भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति, समुद्री सुरक्षा नीति और वैश्विक प्रभाव का महत्वपूर्ण संकेत है। यह यात्रा भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के केंद्र में स्थापित करने के साथ-साथ चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच संतुलन बनाने में भी सहायक होगी। विकास सहायता, रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक संबंध और समुद्री साझेदारी के माध्यम से भारत यह संदेश दे रहा है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और साझा समृद्धि का सबसे भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है।

ट्रंप को सख्त जवाब देने से हम क्यों हिचक रहे?

विकास मिश्रा

यह बात जगजाहिर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करते हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका, भारत को क्षति पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका का कहना है कि सोलर मॉड्यूल, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील और टेक्सटाइल्स में भारत अपनी जरूरतों से ज्यादा निर्माण कर रहा है। भारत का जवाब सधा हुआ है कि हम अपनी विशाल आबादी की जरूरतों के अनुसार उत्पादन करते हैं।

मगर असली सवाल यह है कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरह का जवाब ट्रम्प को दिया है, या एक समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में बैठकर जैसा जवाब ट्रम्प को दिया था, वैसा जवाब देने में हम क्यों हिचकते रहे हैं? हमें यह बात क्यों समझ में नहीं आती कि ताली दोनों हाथों से बजती है! ट्रम्प हमारी हथेली मरोड़ने पर आमादा है और हम ताली बजाने की इच्छा पाले बैठे हैं?

विश्व राजनीति में अभी एक के बाद एक कई घटनाएं हुईं। खास तौर पर तीन घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू साइन होने के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर हमला किया जबकि एमओयू के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेबनान पर हमले को लेकर ट्रम्प बेहद नाराज हुए और नेतन्याहू के लिए बहुत ही सख्त शब्दों का उपयोग किया। आमतौर पर मान्यता यही है कि इजराइल वही करता है जो अमेरिका चाहता है। वह किसी भी हालत में अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कुछ नही कर सकता। मगर नेतन्याहू ने क्या जवाब दिया?

उन्होंने कहा कि न तो ट्रंप उनके इशारों पर काम करते हैं और न ही ट्रंप के इशारों पर वे काम करते हैं। दोनों देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के आधार पर स्वतंत्र फैसले लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर दोनों देश सहमत ही हों! साथ में नेतन्याहू ने ये भी जोड़ा कि कोई भी दबाव इजराइल को अपनी रक्षा करने से नहीं रोक सकता। यानी नेतन्याहू का संदेश बहुत स्पष्ट है कि वे वही करेंगे जे उन्हें इजराइल के हित में लगता है।

अब जरा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रकरण पर नजर डालिए। जी-7 शिखर सम्मेलन में ट्रम्प और मेलोनी की मुलाकात हुई। सब कुशलमंगल ही था लेकिन सम्मेलन के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि शिखर सम्मेलन

के दौरान मेलोनी ने साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ाकर मिन्नत की थी। जरा शब्दों पर गौर करिए- गिड़गिड़ाकर मिन्नत की। निश्चय ही ये शब्द मेलोनी को कमतर बताने के लिए उपयोग में लाए गए! मेलोनी के अपमान का मतलब क्या था? मतलब था इटली का अपमान! मेलोनी ने करारा जवाब दिया और कहा कि न तो मैं और न ही इटली कभी किसी के आगे भीख मांगते या गिड़गिड़ाते हैं।

मेलोनी ने ट्रम्प के इस बयान को अपने और अपने देश के सम्मान पर ठेस बताया। उसके बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने ट्रंप की इस टिप्पणी को गंभीर और अपमानजनक बताते हुए अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया। यहां ध्यान रखिए कि मेलोनी पहले ट्रंप की समर्थक हुआ करती थीं। लेकिन मेलोनी ने सख्त जवाब देकर यह साबित किया है कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछन् नहीं होता। मेलोनी ने यहां तक कहा कि न जाने क्यों ट्रम्प अपने सहयोगियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? हम सब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले दो दशकों में अमेरिका ने खुद यह कोशिश की कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर हों। चीन के खिलाफ अमेरिकी रणनीति में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया।

रिश्ते बेहतरी की तरफ बढ़े भी लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि ट्रम्प के लिए भारत की कोई खास अहमियत नहीं है। कम से कम मौजूदा वक्त में तो ऐसा ही है। एक के बाद उन्होंने ऐसे निर्णय भी लिए हैं भारत के लिए अमेरिकी संदेश माना जाना चाहिए। अमेरिका के यूएस पैसिफिक कमांड का नाम 2018 में इंडो यूएस पैसिफिक कमांड किया गया था ताकि भारत को प्रमुखता दी जा सके लेकिन अमेरिका ने कमान के नाम में से इंडो शब्द निकाल दिया। हालांकि भारत की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है लेकिन भावनात्क झटका तो यह है ही!

अमेरिका लगातार यह कहता रहा है कि भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी बेहतर हो रही है, बढ़ रही है लेकिन दूसरी ओर उसकी हरकतें ऐसी हैं कि शंका होती है कि अमेरिका हमारे साथ कर क्या रहा है? आपको याद ही होगा कि 2019 में अमेरिका ने भारत की जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज स्टेटस को खत्म कर दिया। इसके तहत भारत को करीब 6 I3 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात को अमेरिकी बाजार में विशेष सुविधाएं मिलती थी। 2021 में अमेरिकी नौसेना ने लक्षद्वीप से कोई सवा सौ मील दूर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चलाया और लगे हाथ दावा भी किया कि उसने इसके लिए भारत से अनुमति नहीं ली थी। आपको याद ही होगा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस से भारतीय तेल की खरीदी पर कितना हंगामा मचाया!

हाल के दिनों में अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाया है, उससे हालांकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसकी खुद की नीयत स्पष्ट हो रही है। सच यही है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत अमेरिका को खटक रही है। उसे लग रहा है कि किसी दिन भारत भी चीन की तरह उसके लिए चुनौती न बन जाए! सारी तिकड़म इसीलिए है कि भारत की रफ्तार को किसी न किसी तरह रोका जाए। इसीलिए तो अब वो कह रहा है कि भारत कई क्षेत्रों में अपनी जरूरत से ज्यादा निर्माण कर रहा है। भारत को कहना चाहिए कि हां, हम कर रहे हैं। तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है?

और हां, अमेरिका को याद रखना चाहिए कि उसके तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को धमकाने की बहुत कोशिश की थी। पाकिस्तान के समर्थन में बंगाल की खाड़ी में अपना सातवां बेड़ा भी भेजा था। लेकिन क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया और निक्सन देखते रह गए। भारत की ताकत को कम करके मत आंकिए मि. ट्रम्प!

आखिर नागरिकता साबित करने के लिए कौन-सा दस्तावेज वैध?

सौरभ वार्ष्णेय

भारत में नागरिकता को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि पासपोर्ट अपने-आप में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं है, विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि नागरिकता का निर्धारण केवल किसी एक दस्तावेज़ से नहीं, बल्कि कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र परीक्षण के आधार पर होता है। यह विवाद केवल कानूनी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिकों के भरोसे से भी जुड़ा है। आम नागरिक का सबसे बड़ा सवाल यही है—यदि आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट भी अंतिम प्रमाण नहीं हैं, तो आखिर भारतीय नागरिकता सिद्ध कैसे होगी? लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति नागरिक का विश्वास होता है। यदि नागरिक को अपने ही अधिकारों के प्रमाण को लेकर असमंजस रहे, तो यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कही जा सकती। इसलिए समय की मांग है कि नागरिकता प्रमाणन की प्रक्रिया स्पष्ट, सर्वसुलभ और विवाद-मुक्त बनाई जाए, ताकि किसी भी भारतीय को अपनी नागरिकता साबित करने के प्रश्न पर अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पहचान और नागरिकता एक जैसी नहीं हैं। आधार कार्ड आपकी पहचान और निवास का प्रमाण है। वोटर आईडी मतदान के अधिकार का प्रमाण है। पैन कार्ड आयकर संबंधी पहचान है। ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देता है। पासपोर्ट विदेश यात्रा और अंतरराष्ट्रीय पहचान का दस्तावेज़ है। लेकिन इनमें से कोई भी दस्तावेज़ अकेले नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता। आखिर नागरिकता कैसे तय होती है? भारत में नागरिकता का आधार नागरिकता अधिनियम, 1955 है। इस कानून के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख आधार हैं—जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिककरण द्वारा, किसी क्षेत्र के भारत में विलय के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न उठता है तो संबंधित प्राधिकारी उपलब्ध दस्तावेज़ों, जन्म संबंधी अभिलेखों, माता-पिता की नागरिकता, सरकारी रिकॉर्ड तथा अन्य कानूनी साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करता है। कोई एक दस्तावेज़ हर परिस्थिति में निर्णायक नहीं होता। हाल के वर्षों में जन्म प्रमाण पत्र को सबसे महत्वपूर्ण आधार दस्तावेज़ों में माना जाने लगा है, क्योंकि इससे जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। लेकिन जिन लोगों का जन्म दशकों पहले हुआ और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए स्कूल प्रमाणपत्र, भूमि अभिलेख, पारिवारिक रिकॉर्ड, सरकारी सेवा अभिलेख तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ भी परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं। विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद विपक्ष ने प्रश्न उठाया कि यदि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आम नागरिक किस दस्तावेज़ पर भरोसा करे। दूसरी ओर सत्तापक्ष का तर्क है कि दुनिया के अनेक देशों में भी पासपोर्ट नागरिकता निर्धारण का एकमात्र कानूनी आधार नहीं होता और विवाद की स्थिति में मूल नागरिकता रिकॉर्ड ही निर्णायक होते हैं। यह बहस संसद से लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों तक फैल चुकी है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में आज तक ऐसा कोई एकल राष्ट्रीय नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं है जिसे हर स्थिति में अंतिम माना जाए। परिणामस्वरूप लोग आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज़ों को ही नागरिकता का प्रमाण समझ लेते हैं, जबकि कानून की दृष्टि से इनकी भूमिका अलग-अलग है। लोकतंत्र में केवल कानून होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसका स्पष्ट और सरल संप्रेषण भी आवश्यक है। यदि नागरिकों में यह भ्रम बना रहे कि कौन-सा दस्तावेज़ वैध है और कौन-सा नहीं, तो इससे अनावश्यक भय और अफवाहें फैल सकती हैं।

समाचार पचीसा
रायपुर, रविवार 28 जून 2026

तप और वैराग्य

तप और वैराग्य की पतवार के सहारे ही जीवन-रूपी नाव को सहजता से किनारे ले जा सकते हैं। सत्य की प्राप्ति तपस्वी ही कर सकता है। शारीरिक और मानसिक प्रलोभनों से बचने में जिस सहिष्णुता, धैर्य और संयम की आवश्यकता पडती है, उसे जुटा लेने का नाम ही तप है। अकारण शरीर को सताने का नाम तप नहीं है। सताना तो किसी का भी बुरा है, फिर शरीर को व्यथित और संतप्त करने से क्या होगा। तपस्या वह है, जो सत्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के कारण सीमित उपार्जन से निर्वाह करने की स्थिति में मितव्ययिता अपनानी पडती है। इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार और शिरोधार्य करने का नाम ही तो तप- साधना है। इसी प्रकार, वैराग्य का अर्थ घर-परिवार को छोड, विचित्र वेश बनाना या भिक्षाटन करना नहीं है, वरन यह है कि जिस राग-द्वेष की धूप-छांह में सारा जगत हंसता, रोता, अशांत और उद्विग्न रहता है, उस विडंबना से बचते हुए महान लक्ष्य की ओर अनवरत गति से चलते जाना। सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस असत्यमग्न संसार को एक विचित्र प्राणी लगता है। उसे भी अज्ञान के अंधकार में भटकती दुनिया दयनीय लगती है। दोनों का तालमेल नहीं बैठता। यह विसंगति कहीं कटुता उत्पन्न करती है, कहीं तिरस्कार उलीचती है। कहीं अवरोध उत्पन्न करती है, तो कहीं त्रास देती है। इसे उपेक्षापूर्वक देखना वैराग्य है और इस पर भी जो त्रास सहने पडे, उन्हें संतोषपूर्वक सहने का नाम तप है। वैराग्य और तप की पतवार के सहारे विवेकवान व्यक्ति अपनी साधना की नाव खेते हैं और सत्य के परम लक्ष्य तक जा पहुंचते हैं।

जो भक्त करते हैं साई बाबा का व्रत उनके दूर हो जाते हैं कष्ट

कहते हैं अगर साई बाबा का व्रत 9 गुरुवार तक लगातार किया जाए , तो साईं भक्त की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। फिर चाहे वह मनोकामना नौकरी, शादी, स्थानांतरण की हो या फिर किसी भी तरह की। दुख से भरे मन को साईं सहारा देते हैं। गुरुवार का दिन साईं का रहता है और इस दिन जो साईं भक्त व्रत और पूजा करता है। साईं की उस पर विशेष कृपा बरसती है। साईं बाबा का व्रत कोई भी कर सकता है। यहां तक की बच्चें भी साईं के व्रत को कर सकते हैं। साईं अपने भक्तों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, अमीर हो या गरीब सभी बाबा के दर पर आते हैं और झोली भरकर खुशियां ले जाते हैं। साईं बाबा का व्रत एक बार शुरु करने के बाद 9 गुरुवार तक किया जाता है। इस व्रत को आप बीच में नहीं छोड सकते हैं। मुश्किल कैसी भी हो 9 व्रत पूरे तक इसे नहीं छोडा जा सकता है। जब 9 व्रत करते हुए नौ गुरुवार पूरे हो जाएं तो पांच गरीबों को भोजन और अपनी इच्छानुसार दान देना होता है। इसके साथ ही साई बाबा की पुस्तकें भी बांटनी होती हैं। गुरुवार के दिन शुक्लपक्ष या कृष्णपक्ष किसी भी तिथि में व्रत शुरु कर सकते हैं। 9 गुरुवार तक व्रत करने से मकान मिलना, नौकरी मिलना या विदेश यात्रा पर जाना संभव हो पाता है। मान्यता है कि साईं को कुमकुम लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मौली (कलावा या रक्षा सूत्र) बांधने से इंसान मर्यादा में रहता है।

दूध अर्पित करने से वंश की वृद्धि होती है। दही समर्पित करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शहद अर्पित करने से जीवन में मधुरता आती है। साईं बाबा की पूजा करते समय हमेशा दाहिनी और घी का दीपक और बायीं और तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए।

घी का दीपक प्रज्वलित करने से घर में यश और खुशी की आती है और तेल का दीपक प्रज्वलित करने से किसी भी प्रकार की गृहदशा, मंगल दोष शनिदोष दूर होता है।

इस तैरते हुए मंदिर में आने से सुख सृमद्धि बढती है, यही जटायु ने किया था रावण से युद्ध

आँध्रप्रदेश के अनंतपुर में स्थित एक छोटा सा गाँव है, मान्यता है की यह रामायण के समय की वो ही जगह है जहाँ रावण से युद्ध के पश्चात घायल हो के गिद्धराज-जटायू गिरे थे। साथ ही यंहा ये मंदिर सोलहवीं सदी में बना है जो अपने जबरदस्त हस्तकला के लिए जाना जाता है। मंदिर काफी बडे क्षेत्र में फैला है और इसमे नारायण महादेव और वीरभद्रा के तीन अलग अलग मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है।

मंदिर को झूलते हुए मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसमे सत्तर खम्भे लगे है जिसमे से एक हवा में तैर रहा है। इस एक झूलते हुए खम्भे के कारण इसे हैंगिंग टेम्पल कहा जाता है। ये खम्भा पहले हवा में नहीं तैर रहा था पर एक ब्रितानी कारीगर ने जब ये जानना चाहा के ये खम्बे टीके किस पर है और नीचे से सफाई की तो ये खम्भा भी झूल गया, इसका मतलब ये भी है की बाकि के खंभे भी हवा में है।

मंदिर की मान्यता यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है की इसके नीचे से कपडा निकलने से सुख सृमद्धि बढती है। इस मंदिर का निर्माण कि पौराणिक मान्यता यह है की लेपाक्षी परिसर में स्थित विरभद्र मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्तय ने करवाया था। जब राम सीता को तलाशते हुए यहां राम लखन पहुंचे तो उन्होंने उस घायल पक्षी को देख कर कहा 'ले पाक्षी' यानी की उठो पक्षी जो कि एक तेलगु शब्द है। मंदिर से 200 मीटर दूर मेन रोड पर एक ही पत्थर से बनी विशाल नंदी प्रतिमा है जो की 27 फीट लम्बी, 4.5 मीटर ऊंची है। यह एक ही पत्थर से बनी नंदी की सबसे विशाल प्रतिमा है जबकि एक ही पत्थर से बनी दूसरी सबसे बडी प्रतिमा है (गोमतेश्वर सबसे बडी)। एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनी विशाल नागलिंग प्रतिमा भी स्थापित है जो की संभवतया सबसे विशाल नागलिंग प्रतिमा हैं। इस काले ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा में एक शिवलिंग के ऊपर सात फन वाला नाग फन फैलाय बैठा है। मंदिर में स्थित है राम पदचिन्ह जबकि कइयों का मानना है की यह माता सीता के पैरों के निशान है।

जानिये ऐसा क्या हुआ की कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की

एक बार कृष्ण और अर्जुन एक गांव की तरफजा रहे थे तभी अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और उन्हें नहीं। यह सुन कर कृष्ण ने दो पर्वत को सोने में बदल दिया, और अर्जुन से कहा कि वह इसका सारा सोना गाँव वालो के बीच में बाट दे। तब अर्जुन गाँव गए और सारे लोगों से कहा कि वे पर्वत के पास इक्कट्ठा हो जाएं क्योंकि वे सोना बाटने जा रहें हैं।

पांचों पांडवों से ज्यादा बलवान और बुद्धिमान कर्ण से सीखें ये 7 चीजें यह सुन कर गाँव वालो ने अर्जुन की जय जय कार करनी शुरू कर दी और अर्जुन छाती चौडी कर पर्वत की तरफचल दिए। दो दिन और दो रातों तक अर्जुन ने सोने के पर्वत खोदा और खोद कर सोना गाँव वालो में बाटा। इतने से पर्वत पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे गाँव वाले वापस आके कतार में खडे होकर इंतजार करने लगे। अर्जुन अब थक चुके थे लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड रहे थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब वो थोडा आराम करना चाहते हैं इसके बिना वो खुदाई नहीं कर पाएंगे। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा कि सोने के पर्वत को इन गाँव वालों के बीच में बाट दें। गीता के इन उपदेशों को मानिये, जीवन में कभी नहीं होगी आपकी हार कर्ण ने सारे गाँव वालों को बुलाया और कहा कि ये दोनों सोने के पर्वत उनके हैं और उनसे आ कर सोना ले लो। अर्जुन भौंचक्के हो गये और सोचने लगे कि यह ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया।

तभी कृष्ण मुस्कुराये और अर्जुन से बोले कि तम्हे सोने से मोह हो गया था और तुम गाँव वालो को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरुरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है इसका आकार तुम तय कर रहे थे।

ये हैं महाभारत की 10 प्रेम कहानियाँ जो कोई नहीं जानता लेकिन कर्ण ने यह सब नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वह से दूर हट गया। वह नहीं चाहता कि कोई उसकी प्रशंसा करे और ना उसे इस बात से कोई फर्क पडता है कि कोई उसके पीछे उसके बारे में क्या बोलता है। यह एक निशानी है उस आदमी की जो आत्मज्ञान हासिल कर चुका है। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं सौदा कहलाता है। इसलिए दान करो बिना किसी उम्मीद के ।

यमुना नदी, यमराज की बहन है

हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमुना नदी, यमराज की बहन है। जिसका नाम यमी भी है। यमराज और यमी के पिता सूर्य हैं। यमुना नदी का जल पहले साफ, कुछ नीला, कुछ सांवला था, इसलिए इन्हें 'काली गंगा और 'असित' भी कहते हैं। असित एक ऋषि थे। सबसे पहले यमुना नदी को इन्होंने ही खोजा था। तभी से यमुना का एक नाम 'असित' संबोधित किया जाने लगा। यमुना जिसे यमुनोत्री भी कहा जाता है। यह नदी उत्तरकाशी से 30 किमी उत्तर, गढवाल से निकली है। और अंत में इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। जहां यह त्रिवेणी(गंगा, सरस्वती, जमुना या यमुना) कहलाती है। यमुना की सहायक नदियां चम्बल, सेंगर, छोटी सिन्ध, बेतवा और केन हैं। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, काल्पी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। जिस तरह भगवान श्रीकृष्ण को ब्रज संस्कृति का जनक कहा जाता है, ठीक उसी तरह यमुना को जननी का स्थान दिया गया है।

किस करण से कुंभकर्ण सोता था 6 महीनों तक, जानें रहस्य

इंद्र-इंद्र देवताओं के देवता थे लेकिन वे कुंभकर्ण से ईर्षा करते थे क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान और बहादुर था। इसके लिए इंद्र कुंभकर्ण से बदला लेने के लिए सही समय का इंजार कर रहे थे।

यज्ञ-तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रहमा को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और यागा किया।

वरदान या अभिशाप-यज्ञ से प्रसन्न होके तीनो भाइयों को वरदान देने के लिए ब्रहमा प्रकट हुए। और उन्होंने ने कुंभकर्ण से पूछा की उसे क्या वरदान चाहिए। तब कुंभकर्ण ने कहा कि उसे इंद्रासन चाहिए लेकिन उसके मुँह से निद्रासन निकला।

व्याकुल कुंभकर्ण-जब कुंभकर्ण ने इंद्रासन की बजाये निद्रासन कहा तब उसे अपनी गलती का अहसास हुआ की उसने क्या कहा दिया। जब तक उसे कुछ समझ आता ब्रहमा तथाअस्तु बोल चुके थे। हालांकि की कुंभकर्ण ने कहा कि उसकी इच्छा पूरा ना करें लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

इंद्र की चाल-जैसे की हम सब जानते थे कि इंद्र कुंभकर्ण ईर्षा करते थे। जिसके चलते इंद्र ने देवी सरस्वती से जाके अनुरोध किया कि कुंभकर्ण इंद्रासन की बजाये निद्रासन कहे।

कुंभकर्ण की नींद-तभी से कुंभकर्ण 6 महीने की नींद में चले जाने के बाद फिर से 6 महीने के बाद तग जगता रहा और उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह उससे अपनी भूख मिटाता रहा।

केनोपनिषद: कुछ इस तरह पाएं मन की इच्छाओं से आत्मज्ञान

केनोपनिषद को चार खंडो में बांटा गया है। पहले खंड में मन की इच्छाओं, दूसरे खंड में ईश्वर के निराकार रूप, तीसरे खंड में परब्रहमा की सत्त के बारे में और चौथे खंड में विद्या की देवी सरस्वती द्वारा परब्रहम की विजय के बारे में बताया है। जिंदगी में आप ईश्वर के अध्यात्मरूपी प्रकाश से प्रकाशवान हो सकते हैं उसके बारे में बडी ही सरलता सहजता से बताया गया है।

शांतिपाठ

ऊँ अप्यायंतु ममांगानि
वाक्प्राणचक्षुष: श्रोतमथो
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं
ब्रहमोनिषदं माहं ब्रहमा निराकुर्यां
मा मा ब्रहम निराकरोद
निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे
अपिस्तुतदात्मानि निरते य
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु।

यानि मेरे सभी अंग पुष्ट हों और मेरी वाणी, आत्मा, सुनने की शक्ति के साथ पूरी इंद्रियां पुष्ट हों। सभी विद्या ब्रहमा ने उपनिषदों के रूप में दी है। मैं ब्रहमा का निराकरण न करूं, ब्रह्मा मेरा निराकरण न करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है, वह आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में निहित हो, वह मेरे अंदर समा जाए , उपनिषदों में जो धर्म है उसका निराकार आत्मज्ञान मुझ में समा जाए और मेरे कई प्रकार के तापों को शांति मिले।

प्रथम खंड

1.जिसे कोई नेत्र नहीं देखता, किंतु जिसकी सहायता से नेत्र अपने विषय(लक्ष्य) को देखते हैं, उसी को ब्रहमा(ईश्वर) समझना चाहिए। जिसे कोई कान नहीं सुनता, परंतु जिसकी सहायता से कान सुनने का कार्य करते हैं, उसी को ब्रहमा समझो।

2.यह मन किसकी इच्छा से प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है। यह प्राण किसके द्वारा प्रयुक्त होने पर चलता है। यह वाणी किसके द्वारा इच्छा किए जाने पर बोलती है। कौन देव या देवी नेत्रों और कानों को प्रेरित करते हैं। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जावाब मन की इच्छाओं में छिपे हैं। जिन्हें एक सात्विक मनुष्य के अलावा कोई दूसरा नहीं खोज सकता है।

3.जो कानों का भी कान, मन का भी मन और वाणी की भी वाणी है, वहीं प्राणों का भी प्राण और आंखों की भी आंखें हैं। इस विचार को जानकरा धैर्यवान पुरुष मरने के बाद मुक्त होकर अमर हो जाते हैं।

4.जिसके विषय में मन, मनन नहीं कर सकता, पर जिसकी सत्ता से मन, मनन करने का सामर्थ्य रखता है, ऐसा कहा जाता है कि उसी को ब्रहमा समझना चाहिए। जिसे विशेष नामयुक्त ईश्वर की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रहमा नहीं है।

द्वितीय खंड

1.यदि तुम यह समझते हो कि तुम ईश्वर को अच्छी तरह जानते हो, तो निश्चित ही तुम ब्रहम का अल्प रूप ही जानते हो। इसका जो रूप तुम जानते हो और जो रूप देवताओं में जाना जाता है, वह भी कम है। अत: तुम्हारे लिए ईश्वर को विचार करने योग्य है।

2.सभी इंद्रियां ब्रह्मा की सत्ता से ही कार्य करते हैं इसलिए प्रत्येक इंद्रिय के विषय से उसका ही ज्ञान होता है, इसी से वह जाना जाता है, यही उसका ज्ञान है। इसी ब्रहमज्ञान से अमरता प्राप्त होती है।

3.यदि इसी जन्म में ब्रहम को जान लिया जाए तो, तब तो ठीक है। यदि ऐसा न हो पाए तो यह प्राणी के सर्वाधिक हानि की बात है। कहते है ज्ञानी लोग केवल प्राणी में ब्रहम की सत्ता को देखकर, मृत्यु के पश्चात अमर हो जाते हैं।

तृतीय खंड

1.कहते हैं ब्रहम जब यक्ष रूप में आए तो देवता नहीं पहचान सके कि ये कौन हैं। तब देवराज इंद्र बोले की हे अग्निदेव पता लगाओ को यह यक्ष कौन है। अग्नि ने जब यज्ञ से पूछा कि आप कौन हैं तो यक्ष ने कहा हे अग्नि देव आपके नाम के अनुरूप आप में कौन सी शक्ति है। अग्निदेव बोले कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को जला सकता हूं तब यक्ष ने एक तिनका दिया और कहां इसे जलाकर दिखाओ तब अग्नि देव उस तिनके को जलाने में असफल रहे। इसके बाद देवराज इंद्र ने पवन देव को भेजा उन्होंने भी यक्ष से वही प्रश्न किया तब यक्ष बोले कि इस तिनके को उडाओ पवनदेव भी ऐसा करने में जब असफल हुए और जब यक्ष के सामने इंद्र गए तो तब यक्ष अंतर्धान(गायब) हो गए। तब इंद्र ने हिमालय की पुत्री उमा(ब्रहम विद्या) से पूछा कि यह यक्ष कौन है।

उस ब्रहम विद्या ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह ब्रहम हैं, इसकी विजय से ही तुम महिमामय हुए हो। ऐसा कहते हैं कि तभी इंद्र ने जाना कि वह ब्रहमा थे। इंद्र ने सबसे पहले समीप ब्रहमा का स्पर्श किया इसलिए वह देवों में प्रमुख माने गए और उन्हें स्वर्ग का राजा नियुक्त किया गया।

चतुर्थ खंड

1.मन को गतिमान कहा जाता है। यह ब्रहम इस प्रकार मन से ही बार-बार ब्रहम का स्मरण होता है, तथा निरंतर संकल्प किया जाता है।

2.उपनिषद तप, कर्म, वेद और संपूर्ण वेदांग(व्याकरण, ज्योतिष, छंद आदि) यह सब प्रतिष्ठाहैं तथा सत्य उसका घर है।

3.जो निश्चयपूर्वक उपनिषद को इस प्रकार जानता है। वह अपने पापों को नष्ट करके अनंत और महान स्वर्गलोक में चला जाता है।

ऐसा दानव जिसकी मृत्यु न तो पशु और न ही मनुष्य से हुई

ऊँ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्म
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम ।।
ऊँ नृम नृम नृम नर सिंहाय नम: ।

भगवान नृसिंह शक्ति के देवता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को भगवान विष्णु ने 'नृसिंह अवतार' लेकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध किया था। भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश के लिए कई अवतार लिए तथा धर्म की स्थापना की और अपने भक्तों की सदेव संकट आने पर सहायता की।

नृसिंह अवतार

भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश के लिए कई अवतार लिए पर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए ही नृसिंह अवतार लिया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक शक्तिशाली मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहाद था। प्रहाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था।

यह बात जब हिरण्यकशिपु का पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहाद को समझाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी जब प्रहाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया। लेकिन भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखुनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया।

ऐसे करें व्रत

ब्रहम मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए तथा भगवान नृसिंह की विधी विधान के साथ पूजा-अर्चना करनी चाहिए। भगवान नृसिंह तथा लक्ष्मीजी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए , तत्पश्चात वेद मंत्रों से इनकी प्राण-प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। भगवान नृसिंह की पूजा के लिए फल, पुष्प, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत व पीताम्बर रखना चाहिए। गंगाजल, काले तिल, पंच गव्य व हवन सामग्री का पूजन में उपयोग करें। भगवान नृसिंह को प्रसन्न करने के लिए उनके नृसिंह गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के पश्चात एकांत में कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से नृसिंह भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन व्रती को सामर्थ्य अनुसार तिल, स्वर्ण तथा वस्त्रादि का दान देना चाहिए। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति लौकिक दु:खों से मुक्त हो जाता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

उपचुनाव में प्रशांत किशोर लड़ेंगे चुनाव

नईदिल्ली। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. यह ऐलान इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था. आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि अगर पार्टी की सहमति होगी तो वह बांकीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. उन्होंने इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल का पहला जनमत संग्रह बताते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व और सरकार के कामकाज पर जनता के फैसले का चुनाव होगा. प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से नाराज है. उनका कहना है कि लोगों का मानना है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर की जनता ने वोट सम्राट चौधरी के लिए नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के नाम पर दिया था।

राम मंदिर विवाद सपा-कांग्रेस की साजिश: सीएम पाठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राम मंदिर चंदा मामले से जुड़ा विवाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक साजिश का हिस्सा है. उन्होंने सवाल किया कि बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा किए गए चंदे का क्या हुआ, इस पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया. ब्रजेश पाठक ने कहा, बाबरी मस्जिद के लिए भी चंदा इकट्ठा किया गया था. कोई नहीं पूछ रहा है कि उस पैसे का क्या हुआ. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं और मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए सनातन धर्म पर हमला कर रही हैं. उनके ये बयान अयोध्या पुलिस द्वारा राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद आए हैं. यह एफआईआर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिशों के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।

सुनारिया जेल लौटा राम रहीम, छोड़ने पहुंची हनीप्रीत

नईदिल्ली। रोहतक की सुनारिया जेल में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की वापसी हो गई है. 30 दिन की पैरोल पूरी होने के बाद शुक्रवार शाम करीब 5 बजे राम रहीम सुनारिया जेल पहुंचा. इस बार आश्रम की तीन गाड़ियां जेल तक पहुंचीं, जिनमें से तीन गाड़ियां जेल परिसर के अंदर गईं. राम रहीम को जेल छोड़ने हनीप्रीत इंसां भी साथ पहुंची. खास बात यह रही कि इस बार पुलिस सुरक्षा का काफिला साथ नजर नहीं आया. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 25 मई को 30 दिन की पैरोल पर सुनारिया जेल से बाहर आया था. पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार शाम करीब 5 बजे वह वापस रोहतक की सुनारिया जेल पहुंच गया.जानकारी के मुताबिक, इस बार आश्रम की तीन गाड़ियां जेल तक पहुंचीं, जिनमें से दो गाड़ियां जेल परिसर के अंदर गईं. हनिप्रीत इंसां भी राम रहीम को जेल छोड़ने के लिए साथ मौजूद रही।

धार इमामबाड़ा की चाबी मुस्लिम समुदाय को सौंपें: हाईकोर्ट

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को धार जिला प्रशासन को आदेश दिया कि वे विवादित सरकारी इमामबाड़े यानी सामुदायिक सभा स्थल की चाबियां मुस्लिम समुदाय के एक याचिकाकर्ता को 24 घंटे के अंदर सौंप दें, जिससे वे पांच दिनों तक इसका इस्तेमाल कर सकें. हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का यह आदेश मुहर्रम के दौरान उस जगह पर ताजिया बनाने के लिए दायर याचिकाओं पर आया है. जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं और उनके समुदाय को कुछ वक्त के लिए इमामबाड़े का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी. बेंच ने कहा कि अगर उन्हें पांच दिनों यानी 1 जुलाई तक के लिए जगह दी जाती है, तो राज्य सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं होगा. इमामबाड़ा मुस्लिम समुदाय के लिए एक सभा स्थल होता है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर मुहर्रम के दौरान धार्मिक सभाओं और शोक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है।

होर्मुज में फिर युद्ध की आशंका नए ट्रांजिट रूट को लेकर विवाद

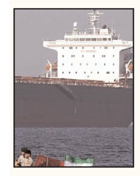

नईदिल्ली। ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नए ट्रांजिट रूट को लेकर विवाद शुरू हो गया है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि ओमान और आईएमओ द्वारा घोषित नए शिपिंग रूट का इस्तेमाल न किया जाए. ईरान कह रहा है कि बिना उसकी अनुमति के कोई भी नया रूट नहीं चलेगा. इस बीच, ब्रिटिश सेना ने बताया है कि ओमान के पास एक जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की मैरीटाइम एजेंसी आईएमओ ने फंसे हुए जहाजों को निकालने का अपना अभियान रोक दिया है. यह हमला उसी समय हुआ जब कुछ घंटे पहले ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी थी कि वे तेहरान की मंजूरी के बिना नए रूट का इस्तेमाल न करें. इस हमले के बाद होर्मुज स्ट्रेट से फंसे जहाजों को निकालने की योजना पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है. उधर, ओमान ने कहा है कि नया रूट अस्थाई है. जहाजों की सुरक्षा के लिए है. इस फैसले से करीब 11 हजार नाविकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

जेपी नड्डा 29 को करेंगे आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च

भारत में डिजिटल हेल्थ क्रांति की नई शुरुआत!

नईदिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा 29 जून को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहल शुरू करेंगे, जो भारत के डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में एक बड़ी प्रगति होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) और नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर ईएचआर स्टैंडर्ड्स (NRCeS) द्वारा शुरू की गई इन पहलों का मकसद हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना और देश भर में स्वास्थ्य के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने की गति को तेज करना है।

इस लॉन्च इवेंट में राज्य के प्रतिनिधि, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, हेल्थकेयर लीडर्स, टेक्नोलॉजी पार्टनर, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और स्टेकहोल्डर्स एक साथ आएंगे। इसका मकसद एक ऐसे हेल्थकेयर सिस्टम की दिशा में हुई प्रगति को उजागर करना है जो आपस में जुड़ा हो और जिसमें अलग-अलग सिस्टम एक-दूसरे के साथ आसानी से काम कर सकें। इस दौरान जो पहल शुरू की जाएंगी, उनमें नागरिकों के लिए ऐप्स, सर्विस देने वालों के लिए टूल्स, इंटरऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्क, रजिस्ट्रियां और डेटा स्टैंडर्ड्स शामिल होंगे। इनसे नागरिकों, हेल्थकेयर सर्विस देने वालों, इंश्योरेंस कंपनियों, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक्सेस, दक्षता और इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाया जा सकेगा।

नागरिकों के लिए एक व्यापक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन (पीएचआर), %आरोग्य सेतु 2.0% पर खास ध्यान दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान बने भरोसे को आगे बढ़ाते हुए, यह अपडेटेड ऐप कई डिजिटल हेल्थ सेवाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म देता है। यह एप्लीकेशन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) बनाने और उसे मैनेज करने, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को देखने और शेयर करने, सहमति-आधारित हेल्थ जानकारी के आदान-प्रदान, एआई-पावर्ड इनसाइट्स, स्मार्ट हेल्थ रिपोर्ट्स, पहनने योग्य डिवाइस (वेयरेबल डिवाइस) के साथ इंटीग्रेशन, स्कैन एंड रजिस्टर के ज़रिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन, स्कैन एंड पे के ज़रिए अस्पताल के पेमेंट, दवा लेने के रिमाइंडर और परिवार की हेल्थ मैनेजमेंट की सुविधा देता है।

यह आस-पास की हेल्थकेयर सुविधाओं, डॉक्टरों, एम्बुलेंस सेवाओं, उपलब्ध यूनिट वाले ब्लड बैंकों और जन औषधि केंद्रों को खोजने की सुविधा भी देता है। इसमें पीएमजेएवाय सेवाओं का एक्सेस भी शामिल है, जिससे एम्पैनल्ड अस्पतालों को खोजना, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाय वॉलेट का इस्तेमाल करना और आयुष्मान सीएपीएफ पॉलिसी की जानकारी के साथ-साथ अन्य हेल्थकेयर सेवाओं का लाभ उठाना संभव हो जाता है। बेहतर बनाया गया आयुष्मान ऐप, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाय) के लाभार्थियों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यह पात्रता की जांच, कार्ड से जुड़ी सेवाएं, इलाज का इतिहास, अस्पताल खोजने की सुविधा, शिकायत निवारण और लाभार्थी सहायता जैसी सुविधाएं देगा।

मोदी सरकार फिलिस्तीन पर चुप क्यों?

सोनिया गांधी ने 20 हजार बच्चों की मौत पर उठाए सवाल

नईदिल्ली। राहुल गांधी ने शनिवार (27 जून) को आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा कि इंडिया धीरे-धीरे इजरायल के रणनीतिक प्रभाव के दायरे में जा रहा है, जबकि दुनिया का बड़ा हिस्सा उससे दूरी बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा को इतिहास एक चौंकाने वाले रणनीतिक फैसले के रूप में देख सकता है। राहुल गांधी ने गाजा में फिलिस्तीनी बच्चों और आम नागरिकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जतायी। उन्होंने आगे लिखा कि भारत की आत्मा और उसकी परंपरा यही कहती है कि हमें अपने फिलिस्तीनी भाइयों-बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए।

तो अब सवाल उठता है कि सोनिया गांधी ने आखिर इस आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा कि राहुल गांधी को ये बातें कहनी पड़ी। तो आइए आपको बताते हैं। सोनिया गांधी ने गाजा के मामले में मोदी सरकार की लगातार चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भारत को फिलिस्तीनियों के समर्थन में स्पष्ट और मुखर रुख अपनाना चाहिए, साथ ही गाजा और वेस्ट बैंक में हो रही घटनाओं पर ग्लोबल ओपिनियन को देखते हुए रिएक्ट करना चाहिए। सोनिया ने एक इंग्लिस डेली के लिये लिखे लेख में संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की हालिया रिपोर्ट का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गाजा में बच्चों को एक प्लान के तहत निशाना बनाया जा रहा है और वहां की मानवीय स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है।

सोनिया गांधी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई नरसंहार जैसी है। उन्होंने बताया कि जून 2026 में आयोग ने फिर कहा कि इजरायल की नीतियों और सैन्य कार्रवाई का असर ऐसा है, जिससे गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो रहा है और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस आयोग की अध्यक्षता अब पूर्व न्यायाधीश एस। मुरलीधर कर रहे हैं और 94 पन्नों की इस रिपोर्ट को पढ़ना बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला अनुभव है।

सोनिया गांधी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में गाजा में हुई तबाही की बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। उनके मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक करीब 20 हजार बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 44 हजार से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। इनमें से कई बच्चों को ऐसी चोटें लगी हैं, जिनके कारण वे पूरी जिंदगी दिव्यांग रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को नुकसान पहुंचना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा बताया गया है। सोनिया गांधी के अनुसार, मरने और घायल होने वालों में बड़ी संख्या बच्चों की है। गाजा के लगभग सभी स्कूल बर्बाद हो चुके हैं और अस्पतालों समेत स्वास्थ्य व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि कई वेस्टर्न कंट्री ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी है, कई देशों ने इजराइल के साथ अपने संबंधों की समीक्षा की है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजराइल की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारत इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस। मुरलीधर की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

सोनिया गांधी के गाजा रुख पर भाजपा का पलटवार

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को कांग्रेस पर पलटवार किया। यह प्रतिक्रिया कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस लेख के बाद आई, जो द इंडियन एक्सप्रेस में गाजा युद्ध, इज़राइल और भारत की विदेश नीति पर छपा था। भाजपा ने कांग्रेस पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामलों में भी वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी के लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस गाजा पर तो बोलती है, लेकिन ढाका में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहती है। उन्होंने पार्टी पर विदेश नीति को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया।

पूनावाला ने कहा कि इससे उनका दोहरा रवैया पता चलता है। यहाँ भी वे वोट बैंक की राजनीति के आधार पर विदेश नीति तय करना चाहते हैं। भारत ने गाज़ा के मामले में हमेशा एक स्पष्ट रुख अपनाया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वोट दिया है और इसके अलावा मानवीय सहायता भी दी है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को फ़िलिस्तीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत की विदेश नीति की वजह से ही देश वैश्विक संघर्षों में सभी पक्षों के साथ बातचीत बनाए रखने में सक्षम रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत ऐसी स्थिति में है कि वह फ़िलिस्तीन और इज़राइल, दोनों से बात कर सकता है। वह यूक्रेन और रूस, दोनों से बात कर सकता है। वह अमेरिका और ईरान, दोनों से बात कर सकता है। आज हम गुटनिरपेक्ष नहीं हैं, बल्कि सभी के साथ जुड़े हुए हैं। पूनावाला ने कांग्रेस पर भारत की विदेश नीति के मामले में सस्ती वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि लेकिन भारत की विदेश नीति पर सस्ती वोट बैंक की राजनीति करना कांग्रेस की आदत बन गई है।

द इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में सोनिया गांधी ने गाज़ा संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के रुख की आलोचना की। कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाक़ों पर यूएन के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि गाज़ा में इज़राइल की कार्रवाई का मकसद बच्चों को निशाना बनाकर फ़िलिस्तीनियों के अस्तित्व को ही खत्म करना था।

खेल
प्रमुख समाचार

फीफा वर्ल्ड कप : फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हराया

टोरंटो/बॉस्टन। स्ट्राइकर उस्मान डेम्बेले ने पहले हाफ में ही हैट्रिक बनाई जिससे फ्रांस ने विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप आई में नॉर्वे को 4-1 से हराकर अपना विजय अभियान जारी रखा। डेम्बेले ने सातवें, 20वें और 32वें मिनट में गोल किए। उनके एक गोल में काइलियन एमबाप्पे ने मदद की। विश्व कप में पिछले 32 वर्षों में यह पहला अवसर था जबकि किसी खिलाड़ी ने पहले हाफ में ही हैट्रिक बनाई। इससे पहले 1994 में अमेरिका में खेले गए विश्व कप में रूस के फॉरवर्ड ओलेग सालेन्को ने कैमरून के खिलाफ अपने पांच में से तीन गोल शुरुआती 45 मिनट में किए थे।

डेम्बेले इस तरह से लियोनेल मेस्सी और अपने साथी एमबाप्पे के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल हो गए हैं। डेम्बेले ने कहा, ''यह एक अनूठा क्षण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमने ग्रुप चरण में पहल स्थान पर रहकर अगले दौर में प्रवेश किया। अब हमारा ध्यान अगले मैच पर है जो सबसे महत्वपूर्ण है।'' फ्रांस और नॉर्वे पहले ही नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर चुके थे और इस मैच से ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम का फैसला होना था। फ्रांस की टीम ने दबदबा बनाए रखा। उसकी तरफ से चौथा गोल दूसरे हाफ के इंजुरी टाइम में डेसिरे डोउ ने किया। नॉर्वे के लिए एकमात्र गोल थैलो आसगार्ड ने 21वें मिनट में किया।

फ्रांस ने तीन मैचों में 10 गोल किए हैं। डेम्बेले ने कहा, ''हम अपने सभी मैच जीतना चाहते हैं, लेकिन हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे।'' पिछले साल यूरोप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में बैलोन डीओर जीतने वाले और इस साल के विश्व कप में चार गोल कर चुके डेम्बेले 65वें मिनट में मैदान से बाहर चले गए। उनकी जगह ब्रैडली बारकोला मैदान में उतरे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

भारत की अर्थव्यवस्था रहेगी मजबूत : ईवाई

नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजारों में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति बहाल होने और घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद के साथ चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6 से 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्तीय सेवा कंपनी ईवाई की रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। ईवाई इकॉनमी वॉच शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें अपेक्षाकृत निचले स्तर पर स्थिर रहती हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य हो जाती है, तो भारत की आर्थिक वृद्धि की सकारात्मक गति फिर से मजबूत हो सकती है। ईवाई ने कहा कि बाहरी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियाद और निजी क्षेत्र की निरंतर सक्रियता के कारण उल्लेखनीय मजबूती दिखा रही है।

भारतीय फिनटेक कंपनियों की नजर अब ग्लोबल मार्केट पर

नईदिल्ली। भारत की वित्तीय तकनीकी (फिनटेक) कंपनियां दुनिया के कुछ सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में लाइसेंस हासिल करने पर विचार कर रही हैं। ये कंपनियां अपने मौजूदा सीमा पार कारोबार से आगे बढ़कर डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहती हैं। उत्तर अमेरिका, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में अपनी मौजूदगी बनाने के बाद फिनटेक कंपनियां अब इन बाजारों में सीधे काम करने, अपने मौजूदा सीमा पार कारोबार को आगे बढ़ाने और कई देशों में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे स्ट्राइप और पेपाल जैसी वैश्विक भुगतान कंपनियों ने अपनाया है। भारत की फिनटेक कंपनी स्काईडो टेक्नोलॉजीज ने बीते मंगलवार को बताया था कि उसे कनाडा में भुगतान लाइसेंस मिला है।

अगले हफ्ते टाटा-महिंद्रा-बजाज समेत 46 कंपनियां बांटेगी डिविडेंड

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए जून का आखिरी और जुलाई का पहला हफ्ता बेहद मुनाफेदार साबित होने वाला है। अगर आप भी शेयरों से होने वाली नियमित और सुरक्षित कमाई यानी डिविडेंड पर नजर रखते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में शामिल कई कंपनियों के शेयर आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। आने वाले दिनों में देश की 46 जानी-मानी कंपनियां अपने निवेशकों को मुनाफे का हिस्सा बांटने जा रही हैं। इस लिस्ट में टाटा, महिंद्रा, बजाज, बायोकॉन और रेमंड जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों से लेकर कई बेहतरीन मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियां शामिल हैं। चूंकि इस आधिकारिक सूची में कुछ कंपनियां फाइनल डिविडेंड के साथ-साथ स्पेशल डिविडेंड भी दे रही हैं, इसलिए अगले कुछ दिनों में कुल 49 बार डिविडेंड का भुगतान निवेशकों के खातों के लिए प्रोसेस किया जाएगा।

युद्ध थमने से वैकल्पिक निवेश फंडों में लौटी रौनक

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष के कारण पिछले कुछ महीनों से वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश जुटाने की रफ्तार धीमी थी। लेकिन अब एआईएफ प्रबंधकों को निवेशकों के मनोबल में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि जिन निवेशकों ने पहले अपना निवेश रोक दिया था, वे अब धीरे-धीरे फिर से निवेश करने लगे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता पहले से बेहतर हो रही है और दुनिया भर के जोखिमों को लेकर स्थिति ज्यादा साफ हुई है जिससे निवेशक, खासकर अति धनाढ्य लोग (एचएनआई), फिर से निजी बाजार में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एआईएफ ऐसे फंड होते हैं जो गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, रियल एस्टेट और जटिल निवेश रणनीतियों जैसे विशेष क्षेत्रों में निवेश करते हैं।

निजी इंफ्रा निवेश की वापसी को संस्थागत रूप से तैयार हो भारत

विनायक चटर्जी

पीपीपी यानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी अब देश के बुनियादी ढांचा विकास में निजी निवेश का संकेत देने वाला एक स्वीकृत संक्षिप्त रूप बन चुका है। भारत के ब्रिटिशकालीन बुनियादी ढांचे के निर्माण में कई परियोजनाएं निजी उपक्रमों के रूप में सामने आई थीं। गारंटीशुदा रिटर्न वाले स्टर्लिंग बॉन्ड्स ने रेलमार्ग, ट्रामवे और बिजली वितरण को वित्तपोषित और संचालित किया। टाटा पावर की स्थापना 1911 में हुई थी। अन्य निजी बिजली संयंत्र भी मौजूद थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के बुनियादी ढांचे में निजी पूंजी का उतारचढ़ाव का सफर आठ चरणों में सामने आया।

इकलौता निर्माता राज्य (1947-1992): 1950 में स्थापित योजना आयोग ने अधिकांश राष्ट्रीय निवेश निर्णयों को नियंत्रित किया। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश हुआ लेकिन यह सार्वजनिक धन से हुआ। ऐसी परियोजनाओं में विशाल जलविद्युत परियोजनाएं और रेलवे नेटवर्क का विस्तार शामिल था, लेकिन निजी पूंजी इसमें शामिल नहीं थी। 1991 के उदारीकरण कदमों के बाद सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में तेजी आने पर नीति-निर्माताओं ने निजी पूंजी की भागीदारी पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया क्योंकि बुनियादी ढांचे की कमी एक चेतावनी के रूप में सामने थी।

पीपीपी का आरंभ (1992-1997): इस समय निजी क्षेत्र को शामिल करना नीतिगत हलकों में गति पकड़ने लगा। उस दौर में पीपीपी के प्रयोग अपने पैमाने के लिहाज से नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण थे। आठ निजी फास्ट ट्रैक बिजली परियोजनाओं में से केवल दो ही बनीं। जीवीके का 216-मेगावॉट जेगुरुपाडु संयंत्र बिजली खरीद समझौते के तहत एक

शुरुआती प्रायोगिक स्वरूप बना। आईएलऐंडएफएस ने मध्य प्रदेश में राऊ और पीथमपुर के बीच 12 किलोमीटर लंबी टोल सड़क बनाई जो भारत का पहला निजी टोल परिचालन था। 1996 में राकेश मोहन विशेषज्ञ समूह ने निष्कर्ष निकाला कि केवल सार्वजनिक बजट भारत के बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित नहीं कर सकते।

पीपीपी का उद्भव (1997-2007): 1997 में पीपीपी ने निर्णायक मोड़ लिया जब देश के पहले समर्पित अधोसंरचना वित्तपोषक के रूप में आईडीएफसी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य निजी पूंजी को अधोसंरचना की ओर ले जाना था। उसी वर्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना की गई जो पहला स्वतंत्र अधोसंरचना नियामक था। बंदरगाह शुल्क और निजी क्षेत्र की भागीदारी की निगरानी के लिए प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण का गठन किया गया।

न्हावा शेवा के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने भारत के पहले बड़े निजी बंदरगाह परिचालन अधिकार पर हस्ताक्षर किए। बिजली अधिनियम 2003 ने उत्पादन और वितरण को लाइसेंस-मुक्त कर दिया, जिससे बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का मार्ग खुला। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सड़क परियोजनाओं में निजी पूंजी आकर्षित करने के लिए नोडल एजेंसी बन गया।

पीपीपी का शिखर (2007-2012): प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अधोसंरचना डेवलपर्स से कारोबारी उत्साह दिखाने का आह्वान किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना ने अधोसंरचना निवेश को जीडीपी के 5 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य रखा। कुल अधोसंरचना निवेश में निजी पूंजी का हिस्सा 22 फीसदी से बढ़कर 37 फीसदी हो गया। एनएचएआई का पीपीपी कार्यक्रम सड़कों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्वर्णकाल साबित हुआ।

जीएमआर ने दिल्ली हवाई अड्डे को रूपांतरित किया जबकि जीवीके ने मुंबई हवाई अड्डे का पुनर्विकास किया। दोनों मामलों में दीर्घकालिक पीपीपी परिचालन अधिकार दिए गए। मुंद्रा बंदरगाह ने दिखाया कि निजी क्षेत्र परिवर्तनकारी बदलाव ला सकता है। बैंकों के जबरदस्त ऋण वितरण के चलते अवसंरचना निवेश जीडीपी के 7 फीसदी से ऊपर चला गया। थोड़े समय के लिए भारत दुनिया के सबसे बड़े पीपीपी बाजारों में से एक बन गया।

नक्सल मुक्त बस्तर के नव निर्माण में समाज निभाए अग्रणी भूमिका : उप मुख्यमंत्री शर्मा

■ नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक में सामाजिक एकता, वन संरक्षण और देवस्थलों के संरक्षण पर दिया जोर*

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त हो रहे बस्तर के नव निर्माण में समाज की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। विकास, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के लिए समाज को संगठित होकर आगे आना होगा। उन्होंने यह बात आज नारायणपुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक को संबोधित करते हुए कही।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद कुछ लोग यह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जंगलों की कटाई होगी या बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने समाज प्रमुखों से ऐसे भ्रामक प्रचार से सतर्क रहने और लोगों को सही जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस्तर के नवनिर्माण का जिम्मा अब बस्तर के युवाओं के मजबूत कंधों पर टिका है और सरकार विकास के साथ-साथ जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर आदिवासी परंपरा का पालन करने वाले लोगों और उससे अलग हो चुके लोगों के बीच अनावश्यक द्वंद की स्थिति बन रही है। यह समाज के हित में नहीं है। समाज प्रमुखों को आगे आकर आपसी वैमनस्य समाप्त करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ने सामाजिक स्थलों एवं देवस्थलों का राजस्व अभिलेखों में चिन्हांकन कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में शासन और प्रशासन के सहयोग से देवभूमियों का सफलतापूर्वक चिन्हांकन कराया जा रहा है। इसी तर्ज पर नारायणपुर में भी सभी समाज प्रमुख मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों का चिन्हांकन शीघ्र पूरा हो सके और भविष्य में उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के दौरान समाज प्रमुखों द्वारा गढ़िया बाबा के देवस्थल के संरक्षण का विषय उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने तत्काल बाउंड्री वॉल, नलकूप तथा सोलर लाइट की व्यवस्था कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्रों का संरक्षण समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

उप मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण को समाज का साझा दायित्व बताते हुए कहा कि जंगलों को बचाने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वैज्ञानिक तरीके से लघु वनोपजों का संग्रहण एवं दोहन किया जाए तो वन भी सुरक्षित रहेंगे और ग्रामीणों को खेती की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। उन्होंने समाज प्रमुखों से इस विषय पर गांव-गांव लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री शर्मा ने कहा कि जैविक कृषि अपनाने से लोगों का खुद का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, भूमि की उर्वरता बनी रहेगी और जैविक उत्पादों को बाजार में बेहतर मूल्य मिलने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

अमरजीत पर पुरंदर का पलटवार

कहा-प्रदेश अध्यक्ष बनने की चाह में कर रहे बयानबाजी

रायपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होने कहा है कि अमरजीत भाई मेरे प्रिय छोटे भाई हैं। कांग्रेस में जैसा अमरजीत भगत बोलते हैं वैसे पुरंदर बीजेपी में बोलते हैं। वो अपना समय 18 से लेकर 23 का कार्यकाल याद करें। बहुत नाक रगड़े थे तब वो मंत्री बन पाए थे।

विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा, अपने 5 साल और हमारे ढाई साल की तुलना कर लें। किसने कितना काम किया याद आ जाएगा। अमरजीत भगत प्रदेश अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कब बैज हटे और वो अध्यक्ष बने इसलिए वो बयानबाजी कर रहे।

कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में फंडिंग जुटाने का आरोप: विधायक पुरंदर ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में फंडिंग जुटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का असली चेहरा प्रशिक्षण में उजागर हो गया। चंदा कैसे वसूला जाए, कैसे आर्थिक स्थिति मजूबत हो इसकी ट्रेनिंग दी गई। कांग्रेस की ट्रेनिंग में कौन झोला लेकर आ रहा इसकी बात होती है। कांग्रेस की मीटिंग आर्थिक कलेक्शन को लेकर ही होता है।

भाजपा के अंदरखाने में कुछ भी अच्छा नहीं = अमरजीत भगत: बता दें कि प्रदेश भाजपा पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा के अंदरखाने में कुछ भी अच्छा नहीं है। चला चली की बेला है, लोगों में व्याकुलता है। भाजपाके पास रिपोर्ट आई है, जिसमें वह सरकार रिपीट नहीं कर रहे।

मुख्यमंत्री साय से पद्मश्री डॉ. बुधरी ताती ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पद्मश्री डॉ. बुधरी ताती ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के उत्थान, लोक संस्कृति के संरक्षण तथा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डॉ. ताती के दीर्घकालीन एवं उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पद्मश्री डॉ. बुधरी ताती ने अपना संपूर्ण जीवन जनजातीय समाज की सेवा, लोक परंपराओं के संरक्षण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के कार्यों के लिए समर्पित किया है। उनका सेवा भाव, समर्पण और सामाजिक योगदान पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर डॉ. बुधरी ताती ने चार दशक से अधिक समय तक बस्तर अंचल सहित वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सतत कार्य किया है। उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. बुधरी ताती जैसे व्यक्तित्व हमारी समृद्ध जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति और सेवा की परंपरा के सशक्त प्रतीक हैं। उनका जीवन नई पीढ़ी को समाज के प्रति संवेदनशीलता, सेवा और समर्पण का संदेश देता है। डॉ. बुधरी ताती ने जनजातीय समाज के विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर पद्मश्री डॉ. बुधरी ताती के परिजन उपस्थित थे।726

बिना पुनर्वास किसी को नहीं करेंगे बेघर : बृजमोहन

रायपुर। रायपुर के नकटी क्षेत्र में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी और वहां निवासरत परिवारों को मिल रहे बेदखली नोटिस के संबंध में प्रभावित ग्रामीणों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भेंट की। ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस और उसके बाद उत्पन्न स्थिति से सांसद को अवगत कराया। इस गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि, ÷प्रस्तावित कार्यों के लिए किसी को भी बेघर करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है। मैंने पूर्व में भी इस संबंध में शासन को अपना पक्ष स्पष्ट किया है और अब भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस पर चर्चा कर उचित समाधान निकालने का प्रयास करूँगा।

सांसद श्री अग्रवाल ने पीड़ित ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली। जिसमें प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक प्रभावित परिवारों के लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास योजना तैयार न हो जाए, तब तक किसी भी स्थिति में बेदखली की कार्रवाई न की जाए।

श्री अग्रवाल का कहना है कि, जिन परिवारों के पास कोई अन्य आवास नहीं है और जो पूर्णतः बेघर हो जाएंगे, उनकी समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य जन-कल्याण है, न कि किसी को संकट में डालना। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ग्रामीणों से अपील की है कि, जिनके पास अन्य स्थानों पर घर उपलब्ध हैं, वे सरकारी योजनाओं को सुगम बनाने हेतु स्वतः सहयोग करें।ताकि जो वास्तव में जरूरतमंद और भूमिहीन हैं।

भूपेश बघेल ने जिला अध्यक्षों को संगठन के गुर सिखाये

रायपुर। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण के 8वें दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को संगठन के गुरू सिखाये तथा प्रदेश के विभिन्न जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए जिला अध्यक्षों से कहा कि वे आक्रमक तरीके से जनता की लड़ाई लड़े। खड़गे जी, राहुल जी ने आपको संगठन की शक्ति दी है उसका उपयोग करके आप मोदी सरकार और राज्य सरकार के भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाये। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की पांच साल की योजनाओं, कांग्रेस की रीति-नीति इतिहास देश के विकास में कांग्रेस का योगदान पर व्याख्यान दिया।

अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह ने तथा अल्पसंख्यक विभाग के अमीन मेमन, आदिवासी अधिकार, अल्पसंख्यक कल्याण तथा जल, जंगल, जमीन पर व्याख्यान दिया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत प्रशिक्षण स्थल पर प्रतिदिन सभी सत्र में शामिल होते है तथा रात्रि विश्राम भी वहीं करते है।राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रभारी सचिन राव की देखरेख में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू एवं व्यवस्था कमेटी के सदस्य तथा सेवादल के स्वयं सेवक प्रशिक्षण स्थल पर व्यवस्था संभाले हुए है।प्रशिक्षण के 9वें दिन प्रतिभागी जिलाध्यक्ष लखना गांव में श्रमदान करने जायेंगे। प्रशिक्षण शिविर का समापन 10वें दिन 29 जून को होगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

आज 35.98 लाख बच्चें पिएंगे पोलिया की दो बूंद

रायपुर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 28 जून 2026 को पूरे रायपुर जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। जिला स्वास्थ्य समिति ने सभी पालकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को निकटतम बूथ पर ले जाकर दवा अवश्य पिलाएं।

भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन पड़ोसी देशों में अभी भी पोलियो वायरस से ग्रसित बच्चे पाए गए हैं। इससे देश में पोलियो संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इसी खतरे को देखते हुए 0 से 5 वर्ष के बच्चों को प्रतिरक्षित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के समस्त ग्रामों एवं वार्डों में कुल 1381 पोलियो बूथ बनाए जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 04 टीकाकर्मी दो टीमों में बंटकर बच्चों को दवा पिलाएंगे। बूथों की मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक 05 बूथ पर एक सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है।यदि कोई बच्चा 28 जून को बूथ पर दवा पीने से छूट जाता है तो 29 एवं 30 जून को घर-घर भ्रमण कर ऐसे बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। पूरे अभियान की निगरानी एवं मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय के अधिकारी व कर्मचारी करेंगे।

सोसायटियों में किसानों को खाद नहीं मिल रहाः बैज

रायपुर। किसान खाद के लिए भटक रहे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि खाद का टोकन सिस्टम सरकार ने खत्म किया है। किसानों को खाद के लिए सरकार ने लिमिट समाप्त नहीं किया है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद खुले बाजार से भी नहीं मिल रहा है। सोसायटियों में भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा है। सरकार सिर्फ

कागजी दावा कर रही। किसान खाद के लिए भटक रहे, आज भी सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण नहीं कर पाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में उर्वरक का संकट विकराल रूप ले चुका है। सरकार बताये बिना उर्वरक के खेती कैसे करें किसान। प्रदेश में उर्वरक के लिये मारा मारी शुरू हो गयी है। आधा से ज्यादा जून बीत गया किसानों को सोसायटी में खाद नहीं मिल रहा है। किसान बराबर सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से उर्वरक के बारे में गुहार लगा रहे, लेकिन सरकार केवल जुबानी आश्वासन दे रही है। आज भी प्रदेश के आधे से कम सोसायटियों में ही खाद पहुंच पाया है। मानसून आने वाला है, खरीफ में धान की फसल ही राज्य के किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है। यदि खरीफ के सीजन में सरकार किसानों को पर्याप्त उर्वरक नहीं दे पायेगी तो किसानों के सामने साल भर के लिये आजीविका का संकट पैदा हो जायेगा।

29 एवं 30 जून को होगा भव्य रामगढ़ महोत्सव

रायपुर। अंचल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत के प्रतीक रामगढ़ में आषाढ़ के प्रथम दिवस के अवसर पर 29 एवं 30 जून को दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतिष्ठित महोत्सव में प्रदेश की लोकसंस्कृति, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व और पर्यटन की समृद्ध विरासत एक साथ देखने को मिलेगी। महोत्सव के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल करेंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, इतिहासकार, कलाकार, शोधकर्ता, पर्यटक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहेंगे। 29 जून को प्रातः 10:30 बजे अतिथियों के आगमन एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। स्वागत समारोह, अतिथियों के उद्बोधन तथा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं पर आधारित लोकनृत्य, लोकगीत एवं लोकवाद्य प्रस्तुतियां पूरे दिन आकर्षण का केंद्र रहेंगी। महोत्सव के दौरान आगंतुक विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीताबेंगरा गुफा, ऐतिहासिक जोगीमारा गुफा, रामगढ़ पर्वत श्रृंखला तथा अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण करेंगे।

महाराष्ट्र मंडल शुरू करेगा गुरुकुल व गौशाला

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने नई कार्यकारिणी व विभिन्न समितियों के भावी पदाधिकारियों, सामाजिक

कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि मंडल अगले दो सालों में गुरुकुल और गौशाला शुरू करने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। काले मंडल के अगले 10 सालों की कार्ययोजनों को लेकर बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा शंकर नगर बाल वाचनालय की तर्ज पर महाराष्ट्र मंडल रोहिणीपुरम सहित रायपुर के कम से कम तीन स्थानों पर नगर निगम अथवा रायपुर विकास प्राधिकरण की जगह पर भवन बनाकर वहां के लोगों के बीच, बाल संस्कार शिविर, सामाजिक जन जागरण अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करेगा।काले ने कहा कि अगले साल यानी 2027 को महाराष्ट्र मंडल सामाजिक जन जागरण वर्ष के रूप में मनाएगा। सालभर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संगोष्ठी, विचार विमर्श होंगे। मराठी समाज के लोगों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने, संस्कारों व परंपराओं से नए सिरे से अवगत कराने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में नए कार्यकाल में कुछ और नई समितियां बनाईं जा रहीं हैं।

सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा दल लौटा

रायपुर।भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय स्वाभिमान और आध्यात्मिक चेतना को नई ऊर्जा देने वाली छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी ''सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा'' आज सफलता के साथ संपन्न हुई। पांच दिवसीय इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद प्रदेश के सभी जिलों से शामिल 1040 विशिष्टजन सकुशल रायपुर लौटे, जहां रायपुर रेलवे स्टेशन पर उनका आत्मीय, गरिमामय एवं भव्य स्वागत किया गया। यात्रियों के चेहरों पर संतोष, श्रद्धा और आत्मिक आनंद की झलक इस अभिनव यात्रा की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण बनी। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष सांस्कृतिक यात्रा ने केवल श्रद्धालुओं को भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन का अवसर ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और राष्ट्रीय एकात्मता का भी जीवंत अनुभव कराया। यात्रा ने यह संदेश भी दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव को भी समान प्राथमिकता दे रही है।

युवा डिजिटल क्रिएटर्स से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल किया संवाद

डिजिटल दुनिया से विश्व पटल तक पहुंचेगा छत्तीसगढ़

रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराओं को देश-दुनिया तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से लखनपुर (अंबिकापुर) में आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर मीट में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए डिजिटल क्रिएटर्स एवं सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्स से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा को छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण शक्ति बताते हुए प्रदेश के पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक आस्था केंद्रों, लोक संस्कृति और जनजातीय जीवन की सकारात्मक एवं प्रेरणादायी कहानियों को व्यापक स्तर पर साझा करने का आग्रह किया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल माध्यम लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी मंच बन चुका है। सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और पर्यटन को नई पहचान दिलाने का सशक्त उपकरण भी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रकृति, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, धार्मिक आस्था, वन्यजीव और जनजातीय जीवन का अद्भुत संगम है, जिसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने में डिजिटल क्रिएटर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

उन्होंने सभी सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्स से आग्रह किया कि वे अपनी रचनात्मक सामग्री के माध्यम से चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़, कांगेर घाटी, सिरपुर, भोरमदेव, रामगढ़, मैनपाट, बारसूर, चंद्रखुरी, दंतेवाड़ा सहित प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की विशेषताओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करें, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि पर्यटन केवल किसी स्थान का प्रचार नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के रोजगार, हस्तशिल्प, लोक कला, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि से भी सीधे जुड़ा हुआ क्षेत्र है।

संवाद के दौरान राजेश अग्रवाल ने स्वच्छता को सफल पर्यटन की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला बताते हुए कहा कि स्वच्छ पर्यटन स्थल ही पर्यटकों के मन में स्थायी छाप छोड़ते हैं। उन्होंने सभी डिजिटल क्रिएटर्स से अपने सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने तथा पर्यटन स्थलों पर साफ-सफाई बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक यदि अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संकल्प ले, तो छत्तीसगढ़ देश के सबसे स्वच्छ और आकर्षक पर्यटन राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकता है।

ऑटो-ई रिक्शा में क्यूआर कोड व्यवस्था शुरू, 15047 वाहनों का हुआ पंजीयन

रायपुर। राजधानी रायपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिजिटल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। यातायात पुलिस ने ऑटो और ई-रिक्शा वाहनों में क्यूआर कोड लगाने की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों को वाहन और चालक की पूरी जानकारी मोबाइल स्कैन के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी। इस पहल को शहर की यातायात व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत यातायात कार्यालय परिसर कालीबाड़ी में पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला की मौजूदगी में की गई। उन्होंने बताया कि यह योजना शहर में सुरक्षित और व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। प्रथम चरण में ऑटो और ई-रिक्शा का ऑनलाइन पंजीयन किया गया था, जबकि अब दूसरे चरण में वाहनों पर क्यूआर कोड चस्पा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार मात्र 15 दिनों में 15047 ऑटो और ई-रिक्शा वाहनों का ऑनलाइन पंजीयन पूरा किया गया है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस उपलब्धि को देश में पहली बार किसी जिले द्वारा इतनी तेजी से डिजिटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन करने के रूप में देखा जा रहा है।

क्यूआर कोड सिस्टम के माध्यम से यात्री वाहन में बैठने से पहले या यात्रा के दौरान मोबाइल से कोड स्कैन कर चालक का नाम, वाहन नंबर और अन्य जानकारी देख सकेंगे। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और किसी भी आपात स्थिति में वाहन की पहचान करना आसान होगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.